SHRI SUJEET KUMAR: Sir, I introduce the Bill.

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, हम सब "द राइट टू हेल्थ बिल, 2021" के ऊपर बहस कर रहे थे और माननीय संजय सिंह जी बोल रहे थे। इसके पहले मैं उल्लेख करूँ कि यह बिल माननीय मनोज कुमार झा जी द्वारा लाया गया है, आज मनोज जी का जन्मदिन है। मनोज जी, इसके लिए मेरी निजी बधाई और सदन की ओर से भी मैं आपको बधाई देता हूँ। Shri Sanjay Singh, not present. Dr. V. Sivadasan; not present. Prof. Ram Gopal Yadav, not present. Now, Shri Sandosh Kumar P., you had given your name to speak on this subject.

The Right to Health Bill, 2021#

SHRI SANDOSH KUMAR P (Kerala): Sir, I do support the Bill seeking health to make one of the fundamental rights. I don't know why some of the colleagues are opposing the same because it is a universal concept that health must be a fundamental right. The World Health Organisation itself in the year 1946 had highlighted the importance of making health a fundamental right. And, there are many other international conventions also.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN) *in the Chair.*]

Madam, in our country, our Directive Principles of State Policy speak about these things. A number of upper court rulings are also there. So, there is no point in opposing the suggestion to make health a fundamental right. So, what is the Indian reality? We all know that. According to the reports by World Health Organization, 55 million Indians were pushed into poverty due to medical expenses. This is not an exaggerated figure. Of course, it is alarming. But it is a reality. Moreover, if one has to spend 100 rupees for medical expenditure, Rs.63, he or she has to spend out of her pockets. And, comparing with many other countries, our medical expenditure is very high. So, what is the remedy? The remedy is to make health a fundamental right, and we have to spend more on health care. Now, we are spending just 2.1 percentage of the GDP. This is shockingly low. I am not going to argue with figures. So, the Government is not having any financial crunch. I do believe that this Government has enough resources to provide for healthcare. Instead, what is the Government doing? This Ayushman Bharat is just a mechanical copying of the Obama Care Project which was established in America. What we need is a revisit of

Further consideration continued on a motion moved on the 22nd July, 2022.

our health policies. For that, we have to spend more on health, at least six or seven per cent of the GDP on healthcare because in the Preamble of the Constitution itself, there is a term 'dignity'. To live a dignified life, health is very important.

Secondly, as you know, I am sorry to say that there is a nexus among the pharma companies, testing labs and big corporate hospitals. This nexus should be exposed. I am not talking against the pharma companies or big hospitals. But, there is a nexus which actually prevents the public health system from developing. So, we have to think about that also.

Madam, as you know, there are certain health-related superstitions in the country. Some of the political luminaries--I don't want to name them--were actively advocating the usage of cow dung, *gomutra*, etc. This kind of superstitions will not help. They can use them, of course. No one is opposing. But, they should not propagate the faith. Our people will take it seriously. A section of our society may take it seriously. These health-related superstitions must be controlled.

Taking into account all these factors, we need to revisit our health policy and health must be given a top priority and it must be one of the fundamental rights in the Constitution of India. This is what I wanted to say, Madam. Thank you.

डा. अनिल अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आज सबसे पहले तो मैं माननीय मनोज झा जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूं। उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है। मुझे लगता है उन्होंने इसमें जो राइट्स की बात कही है, चूंकि वे बिहार राज्य से आते हैं, शायद वहां की स्थितियां उतनी अच्छी नहीं हैं, जितनी अन्य स्टेट्स में हैं। मनोज झा जी के द्वारा जो बिल लाया गया है, उस पर डा0 अमर पटनायक जी ने लीगल स्थिति पिछली बार क्लियर कर दी थी कि किस प्रकार से इसमें कार्य किया जा सकता है। एक चीज़ मनोज जी ने भी बड़े जोरदार तरीके से उठाई थी कि हम हेल्थ के विषय को स्टेट का विषय मानकर अपनी इतिश्री समझ लेते हैं, लेकिन मनोज जी, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। किसी भी विषय में हम अगर राइट्स दे भी देते हैं, लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर न हो, तो वहां राइट्स देने का कोई फायदा नहीं होता है। उसके लिए हमें एक पॉज़िटिव माहौल बनाना पड़ता है, ताकि लोगों को बगैर राइट्स दिए भी वे सब चीज़ें मिल सकें। दुनिया में बहुत सारी जगह यह देखा गया है कि वहां राइट्स दे दिए गए, लेकिन इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो उनको वे राइट्स देने का फायदा नहीं मिला। मैं इस चीज़ को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा। पूर्ववर्ती सरकारों में मेडिकल के प्रति जो नज़रिया था, वह काफी संकीर्ण था। हर चीज़ के लिए हम लोग विदेश की ओर देखते थे। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी, जो एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनको इसका दर्द पता था, इसलिए इस विषय में उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। वे जानते हैं कि गरीब के लिए किस तरह परिवार चलाना मुश्किल होता है, ऐसे में किसी सदस्य को कहीं बीमारी आ जाए, तो और भी दिक्कत हो जाती है। अभी मुझसे पूर्व जो मित्र बोल रहे थे, उन्होंने भी इस बारे में चर्चा की थी कि लगभग 55 लाख लोगों को इस बीमारी के कारण या अन्य बीमारियों के कारण बहुत

दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मनोज जी, मैं आपको उपसभाध्यक्ष महोदया की मार्फत बताना चाहूंगा कि पहले इस देश में दवाइयां बहुत महंगी थीं, मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत महंगे थे, मेडिकल की सुविधा गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर थी और हम लोग बस किसी प्रकार से काम चलाते थे। माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बहुत अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जिसके बारे में पहले लोग कभी सोचते भी नहीं थे, जेनरिक मेडिसन का नाम बहुत सारे लोगों ने तभी सुना, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बारे में पहल की।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं, जिनकी कीमत लगभग 80 प्रतिशत तक कम हुई है। सॉल्ट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन चूंकि ब्रांड का नाम जुड़ जाता है, इसलिए... मैडम, मुझे कितने मिनट बोलना है?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Your party has four speakers and there are only four minutes for each speaker. So, your time is actually over. लेकिन अब आप कन्क्लूड करिये, मेरे पास चार नाम हैं। I am helpless.

डा. अनिल अग्रवाल : मुझे बताया गया था कि मेरा टाइम लगभग 15 मिनट है, तो मैं...(**व्यवधान**)... आप मुझे दो मिनट का टाइम दीजिए, मैं कन्क्लूड करता हूं।

जहां एक तरफ लोगों को जेनरिक दवाइयों का बैटर प्राइस मिलना शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बैटर प्राइस पर मिलने लगे हैं, इनके प्राइसेज़ काफी घटाये गये हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभी सांसदों और विधायकों, जो विशेषकर भाजपा के हैं, उनको कहा कि आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोद लीजिए, ताकि इन्फ्रास्ट्रक्चर बैटर हो सके।

मैं एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 में पूरे देश में 387 मेडिकल कॉलेजेज़ थे और इनमें 51,348 सीट्स उपलब्ध थीं। आज वर्तमान में हमारे देश में 612 मेडिकल कॉलेजेज़ हैं और 91,927 सीट्स हैं।

महोदया, मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश का इसमें जिक्र करना चाहूंगा, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। 2014 में उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज थे and seats were 3,749. आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उसके अनुसार we have 67 medical colleges and we have very large number of seats. उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज देंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लोगों की हेल्थ के बारे में विचार कर रही है और लोगों को फेसिलिटेट कर रही है। 'योग' और 'आयुष' के माध्यम से लोगों को सशक्त किया जा रहा है, ताकि वे बीमार ही न पड़ें। मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देंगे, अपने आयुष मंत्रालय के माध्यम से लोगों को लिटरेट कर देंगे, तो राइट टू मेडिकल हेल्थ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम लोग ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। हमारा सिद्धांत है - 'पहला सुख निरोगी काया', धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): The next speaker is Dr. L. Hanumanthaiah; not present. Now, Shri Jawhar Sircar.

3.00 P.M.

SHRI JAWHAR SIRCAR (West Bengal): Thank you, Madam. I fully support the Bill moved by Prof. Manoj Jha. And, I would, humbly, like to point out just a couple of small things.

The first one is, Clause 5 of the proposed Bill includes provisions taken from the United Nations. And, health is expanded to cover the Rght to Food, which we have already brought in and, to a large extent, right to water, sanitation, etc. But, it does not include a subtle mention made by the UN on gender. So, we may have to examine it at an appropriate occasion to see whether the economic, cultural and social rights include gender as a part of Right to Health.

India has a lot of firsts among many countries. There is no denial about that. But, India also stands out like a sore thumb as far as certain expenditures are concerned. The expenditure on health, for instance, is pegged at 1-1.5 per cent of the GDP which remains an international shame. It is not that expenditure has not been done. It is a question of aggregating it. It is a question of pinpointing it. I have enough faith in a nation that could eradicate polio, helped the world in eradicating smallpox and has now gone in for a massive venture to give free vaccines. The nation that could do so much, my humble submission to you, to the mover of the Bill, to the Health Minister and others, is to take an overview of what we are doing. We are doing it on separate tracks. We are doing Swachh Bharat on one hand and Har Ghar Jal and health on the other hand. Can we collate all these together as a fundamental right to health, because it is health, ultimately, that would matter when it comes to rights of citizens? If a man or a woman cannot exist in a healthy life then what is the point of showering so many benefits on him? So, my submission would be to take an overview of the way the nation is progressing, not to quibble between the rights of the States, duties of the States and the duty of the Centre. Madam, duties of States and Centre are quibbled around. Even in my morning question, they quibbled around and said that it is for the States to do it. This is a national body. Let us take a national view of the whole thing. Let us set a target and when I say, 'let us', I don't mean the Government of the day only. The Government of the day should take cognizance, should take advice of senior specialists on the other side who are equally concerned about this nation.

Therefore, I plead to the Government and to the House to consider this Bill most favourably. There are a couple of small things here and there. And, incidentally, we have passed a Bill two days ago on the ground that we have an international obligation to fall in line with weapons of mass destruction. We have an international obligation also to ensure right to health. Not one. We have a series of obligations put together. So, I submit to the Government to treat this as a Government proposed Bill and not just pass the Bill, but also make a plan of action for the next five years with the cooperation from all sides of the House, with the goodwill of the people of India and looking at the track record of India as a whole, I am sure, we would be able to tackle this menace and provide a healthy life to every Indian who is born. After all, we are now reaching the status of world's most populous nation. We owe it to them. We owe it to make it a demographic dividend, and not to live as a demographic disaster.

With these words, I support the Bill moved by Prof. Manoj Jha. Thank you for your time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Now, we have hon. Lahar Singh Siroya, not present. Now, Shri Radha Mohan Das Agarwal.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, 67 साल के इस नौजवान ने अगर आज भी सपने देखने नहीं बंद किए, तो यह ...(व्यवधान)...

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : मेरी उम्र 67 साल नहीं, बल्कि 55 साल है। मैंने 1967 में अपनी पैदाइश बतायी थी।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : आपने अपनी पैदाइश बतायी थी, लेकिन मैंने उम्र सुन लिया।

महोदया, 55 साल के इस नौजवान ने अगर आज भी बेहतरी के सपने देखे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इस सदन से बधाई के पात्र तो हैं। जब मैं सांसद नहीं था, 20 साल विधायक था, तब भी मैं मनोज जी को सदन में सुनता था। मैं इनका प्रशंसक था, इसलिए नहीं कि ये अच्छा बोलते थे, बल्कि इसलिए कि ये अच्छी बातें बोलते थे। जब व्यक्ति बहुत लंबे समय तक लगातार अच्छी बातें बोलता है, तो लगता यही है कि वह मूलतः एक अच्छा आदमी होगा। आप भावनाओं में बहकर यह विधेयक लाये हैं। मैं आपकी प्रशंसा करूँगा। जब लेफ्ट के लोग राइट की बात करने लगें, तो स्वाभाविक रूप से, राइट में बैठे हुए लोग इससे आनंदित भी होंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। 'राइट टू हेल्थ' दुनिया की कोई अजूबी बात नहीं है। मैं लोगों को सुन रहा था - कोई डब्ल्यूएचओ कह रहा है, कोई किसी संस्था का नाम ले रहा है, कोई अंतरराष्ट्रीय ऑब्लिगेशन की

बात कर रहा है। भारतीय संस्कृति में राइट टू हेल्थ उस समय था, जब दुनिया गड़ेरियों के स्तर का जीवन जीती थी। जब हमारे प्राचीन शास्त्रों की शुरुआत की गई थी, तब लिखा गया था -

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।"

मनोज जी, यह दुनिया का पहला मानवीय अधिकार था। डब्ल्यूएचओ तो 1948 में आकर बना था। यह इस दुनिया में मानवीय सभ्यता का दिया हुआ पहला मानवीय अधिकार था। अगर इस पूरी धरती पर किसी ने पहली बार यह दिया, तो भारतीय सभ्यता ने दिया - दुनिया का हर आदमी सुखी हो, दुनिया का हर आदमी स्वस्थ हो। 'सर्वे सन्तु निरामयाः', दुनिया का हर आदमी आपस में भ्रातृत्व के भाव से जुड़ा हो। 'सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत', दुनिया में किसी को भी या दुनिया के किसी हिस्से में भी किसी प्रकार का दुख न हो। यह मानव सभ्यता की बेहतरी के इतने सर्वांगीण अधिकार हैं कि हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं। इन चार अधिकारों में आपके सारे अधिकार समाहित हैं। आपने अपने विधेयक में राइट टू वॉटर से लेकर सात-आठ प्वाइंट्स और जोड़े हैं। सूत्र रूप में हमारी सभ्यता ने जो अधिकार दिया है, अगर आप उसे सीधे समझें तो ...हमारे यहाँ ब्रह्मसूत्रों की परंपरा रही है। हम सूत्रों में बोलते हैं, फिर उसके ऊपर ढेर सारे ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ लिखे जाते हैं। हम मानवीय सभ्यता के बारे में क्या सोचते हैं, इन चार वाक्यों में यह बहुत स्पष्ट है।

मैडम उपसभाध्यक्ष जी, 'आदर्श' एक अच्छी चीज़ होती है। जब हम उस आदर्श को जमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं, तब हमें अपनी आर्थिक सीमाओं को देखना पड़ता है। हम सबके मन में यह कल्पना है कि हम इस दुनिया को स्वर्ग बना दें, लेकिन स्वर्ग तभी बनता है, जब हम अच्छे कर्म करके ऊपर जाते हैं। हाँ, हम धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थितियाँ लाने का प्रयास कर सकते हैं। हम इस आदर्श को लेकर चलेंगे और इस आदर्श के नजदीक पहुंचने का अधिकतम प्रयास करेंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। आपका विधेयक ऐसा नहीं है कि यह किसी राजनैतिक सोच से जुटा हो। यह राइट, भाजपा, सपा वगैरह का विधेयक भी नहीं है। भले ही, आप राष्ट्रीय जनता दल के सांसद होंगे... ...(**व्यवधान**)... नहीं, मैं राजनैतिक बात नहीं करूँगा। लेकिन, आपकी पहचान राष्ट्रीय जनता दल की नहीं है। आपका अपना एक वजूद है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, राइट के साथ कह सकता हूँ, जिस गारंटी की आप बात करते हैं, आपका यह विधेयक आपके संगठन के विचारों से उत्प्रेरित नहीं है। जहाँ तक आप पहुंचे हुए हैं, आपका संगठन वहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता है। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झा : इसे संगठन ने ही अपने मेनिफेस्टो में दिया था।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : जी। जो आपके अपने विचार हैं, जो आपने पूरी जिंदगी सीखा है, जो आपका अपना निर्माण हुआ है, उसके तहत आप इस विचार को लेकर आए हैं। हम आपके इस

विचार का स्वागत करते हैं, लेकिन जब हम किसी भी अच्छी बात का जमीनी धरातल पर स्वागत करते हैं, तब हमें देखना होता है कि क्या हम सचमुच सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच सकते हैं। मैं आपको दुनिया के कुछ देशों का उदाहरण दूँगा। अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 57 लाख रुपये है। अब आप यह मत कहिएगा कि डॉक्टर साहब सीधे अमेरिका पहुंच गये। मैं इल्लॉजिकल बातें नहीं करता हूँ। इज़रायल की प्रति व्यक्ति आय 38 लाख रुपये है, जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय 35 लाख रुपये है, जापान की प्रति व्यक्ति आय 27 लाख रुपये है, चाइना की प्रति व्यक्ति आय 9 लाख रुपये है, रूस की प्रति व्यक्ति आय आठ लाख रुपये है और जब मैं उस दिन महंगाई पर बहस कर रहा था, तब मैंने कहा था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय डेढ़ लाख रुपये है। क्या ये 35 लाख वाले, 38 लाख वाले, 53 लाख वाले, 27 लाख वाले अपने-अपने देशों में, अपने-अपने नागरिकों को राइट टू हेल्थ दे पाए? क्या उन्होंने दिया? क्या उनकी देने की मंशा है? दुनिया के इतने समृद्ध देश अगर अपने देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य का यह मौलिक अधिकार नहीं दे सकते हैं, तो डेढ़ लाख प्रति व्यक्ति आय का देश होकर हम उस आदर्श की स्थापना कर देंगे, जो तथाकथित रूप से डब्ल्यूएचओ ने पहली बार किया था, यह सोचना वैसा ही होगा जैसा एक यूटोपियन सोशलिज्म होता है। आप तो उस विचारधारा के बारे में जानते हैं। सोशलिस्टों के आने के पहले एक आदर्श सोशलिज्म चलता था, जिसको हम लोग यूटोपियन सोशलिज्म कहते थे, जिसमें हम कल्पना में दुनिया में सबकी बेहतरी की बात सोच लिया करते थे।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इन देशों का ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ? इन देशों में से एक भी ऐसा देश नहीं है, जिसने स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया हो। किसी छोटे-मोटे देश ने ऐसा किया होगा, जिसकी जनसंख्या 80 लाख, 90 लाख, एकाध करोड़, दो करोड़ होगी, लेकिन हम 140 करोड़ लोग हैं। ऐसा कोई भी देश नहीं है। मैं कुछ देशों का उदाहरण दूँगा। जैसा कि मैंने अमेरिका का ज़िक्र किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में 'अफॉर्डेबल केयर एक्ट' है। उस दिन आप कह रहे थे कि इंश्योरेंस तो होना ही नहीं चाहिए। इंश्योरेंस पूरी दुनिया की स्वास्थ्य सेवा का आधार बना हुआ है। जितने भी देश आज जो थोड़ी-बहुत स्वास्थ्य सेवा दे पा रहे हैं, वे सिर्फ स्वास्थ्य के इंश्योरेंस के माध्यम से दे रहे हैं। अमेरिका ने अफॉर्डेबल केयर एक्ट बनाया और अपने नागरिकों को वह सुविधा निःशुल्क न देकर उस इंश्योरेंस के माध्यम से ही दी। जिन लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, उनसे उस इंश्योरेंस को करवाने के लिए वे प्रति वर्ष अच्छा-खासा पैसा जमा करवाते हैं, जबकि भारत ऐसा नहीं करता है। जब मैं भारत के बारे में बोलूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि भारत दुनिया में कैसा अकेला अजूबा देश हो गया है। आप भी जानते होंगे, आपमें में से कई लोगों के रिश्तेदार अमेरिका में भारतीय नस्ल के होंगे। वे बूढ़े माँ-बाप, जो अमेरिका में अपने बच्चों के पास पहुँच गए हैं, अगर उनका वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, तो अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाएँ इतनी महँगी हैं कि वे लोग वहाँ से आने-जाने का खर्चा वहन करके अपना इलाज कराने यहाँ आते हैं। मेरी अपनी स्वयं की एक मौसेरी सास थी। वह अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका से भारत आई। अभी मैं आज के अख़बार का एक आँकड़ा पढ़ रहा था कि भारत में साढ़े चार-पाँच लाख लोग प्रति वर्ष मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। वे क्यों आते हैं? इसलिए कि जब वे भारत में आकर अपना इलाज कराते हैं, तो उनके सारे खर्चों को मिलाकर भी उन्हें वह खर्चा बहुत कम लगता होगा, क्योंकि कोई थोड़े बड़े खर्चे के लिए अपनी बीमारी लेकर अमेरिका से भारत नहीं आएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से इज़रायल की बड़ी चर्चा होती है कि वह एक आदर्श देश है, जबकि सच्चाई यह है कि इज़रायल के हर नागरिक को इंश्योरेंस कराना होता है और इश्योरेंस का टैक्स भी देना होता है। वह टैक्स इतना अधिक होता है कि बहुत से नागरिक उसको जमा नहीं कर पाते हैं। सरकार उनके इलाज में थोड़ा-बहुत आर्थिक सहयोग करती है, लेकिन मूल खर्चा वे खुद वहन करते हैं।

मैंने यूरोप की बात की है। मैं यूरोप के किसी एक पर्टिकुलर देश की बात नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसके अधिकांश देशों की बात करूँगा। वहाँ अधिकांश नागरिकों को सरकारी नहीं, बल्कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। जब वे इलाज कराते हैं, तो उनकी स्थिति इतनी दयनीय होती है कि जैसे हम लोग प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री को एप्लिकेशन लिखकर पैसा दिलवाते हैं, वैसे ही उनको पैसा दिलवाना पड़ता है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, जहाँ तक रूस की बात है, तो उसकी स्थिति यह है कि वहाँ जितने भी आदमी हैं, उन सबकी तनख्वाहों में से पैसे काट लिए जाते हैं। किसी को पता ही नहीं रहता कि उनकी तनख्वाह से कितना पैसा काटा गया। उसके माध्यम से उनको सेकंडरी और टर्शिअरी नहीं, बल्कि मौलिक स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया जाता है। सबसे बड़ा देश - चीन, जो एक जमाने में अपने आपको वामपंथ का पुरोधा कहता था, 1949 में जब वहाँ क्रांति हुई, तो जो आदर्श आप बताना चाहते हैं, वही आदर्श लेकर वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी चली थी।

वहां जितनी स्वास्थ्य सेवाएं थीं, उन्होंने सबका अधिग्रहण कर लिया था। वहां जितने अस्पताल और क्लीनिक्स थे, सब सरकारी हो गए और चीन ने यह दावा किया कि हम सबको निःशुल्क इलाज देंगे। कुछ दिनों बाद चीन की समझ में आ गया कि उसने जो सपना देख रखा था, वह सपना व्यावहारिक धरातल पर पूरा नहीं होने वाला है। वर्ष 1978 आते-आते चीन ने इस सिस्टम को तोड़ दिया। जिन अस्पतालों का अधिग्रहण कर लिया था, उन्हें बेच दिया। उन्हें प्रॉफिट पर इलाज करने का अधिकार दे दिया और वे सिर्फ टीकाकरण का पैसा अपनी जेब से देते थे। थोड़ा समय और बीता, वर्ष 1990 और वर्ष 2005 आते-आते चीन को यह भी ...(व्यवधान)... मैडम, मेरा आपसे आग्रह है कि आप मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मूलतः बच्चों का डॉक्टर हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : आप बोलिए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज जो यहां नहीं आए हैं..

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : आपको उन्हीं का टाइम मिल रहा है।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : मैं आपकी मदद करने के लिए एक रास्ता निकालता हूं कि आज जो लोग नहीं आए हैं, आप उनका समय मुझे दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : आपको ऑलरेडी टाइम दिया जा चुका है। आप बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : मैं काँग्रेस से भी समय ले लूंगा। यहां पूरी पार्टी है। आप परेशान मत होइए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : डॉक्टर साहब, आप बोलिए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : महोदया, चीन में क्या हुआ! उनको उस एक्ट को भी बदलना पड़ा और वर्ष 2020 आते-आते Law of Promotion of Basic Medical and Healthcare पर आ गए। उस Law of Promotion of Basic Medical and Healthcare में भी ...(**व्यवधान**)... बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): No cross-talk, please. Hon. Member, please address the Chair.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : महोदया, वे हमारे ही हैं। उसके उलट भारत कहां है? एक 'आयुष्मान भारत स्कीम' है, उसका लाभार्थी कौन-कौन है? मनोज जी, आप इस सूची को पलट कर देखिएगा - बिना आश्रय के परिवार, निराश्रित, भीख पर जीवनयापन करने वाले, सिर पर मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप से छुड़ाए गए बंधुआ मज़दूर, कच्ची दीवारों और कच्ची छत के नीचे एक कमरे में रहने वाले लोग, 16 से 59 वर्ष की आयु के ऐसे परिवार जिनमें कोई वयस्क न हो, ऐसे परिवार, जिनकी मुखिया महिला हो और कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो, विकलांग सदस्य और कोई भी सक्षम शरीर वाला वयस्क सदस्य न हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार, भूमिहीन परिवार - जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा दिहाड़ी मज़दूरी से अर्जित करता हो, कूड़ा बीनने वाला परिवार, भिखारी, घरेलू नौकर, गलियों में सामान बेचने वाला, मोची, फेरी वाला, गलियों में काम करने वाला सेवा प्रदाता, निर्माण काम में लगे हुए मज़दूर, प्लम्बर, राजमिस्त्री, मज़दूर, पेन्टर, वैल्डर, सुरक्षा गार्ड, कुली, सिर पर भार ढोने वाले मज़दूर, स्वीपर्स, साफ-सफाई वाले कर्मी, माली, परिवहन कामगार, ड्राइवर, कंडक्टर, ड्राइवर और कंडक्टर के हेल्पर्स, ठेला खींचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दुकानों पर काम करने वाले, छोटे प्रतिष्ठानों के चपरासी, हेल्पर्स, डिलीवरी सहायक, वेटर, इलेक्ट्रीशियन, मकैनिक, असेम्ब्लर, रिपेयरकर्मी, वॉशरमैन और चौकीदार। आप इस पूरी सूची को देख लीजिए।

उपसभाध्यक्ष महोदया, इस सूची में कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचेगा, जिसकी चिंता न करके माननीय मनोज झा जी यह विधेयक यहां लाए होंगे। ये जब विधेयक लाए होंगे, तो इनके दिमाग में देश के गरीब लोग रहे होंगे, यह इनकी बातों से दिखता है। भारत सरकार की जो 'आयुष्मान योजना' है, उसके अंतर्गत 18 करोड़ 54 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। एक कार्ड एक परिवार पर लागू होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर उसका लाभ ले सकते हैं। 5 लाख रुपये तक की अधिकतम सीमा तक निःशुल्क इलाज मिलता है। आप इस 5 लाख रुपये को 50-50 हज़ार रुपये के 10 टुकड़ों में भी बांटकर लाभ ले सकते हैं। इलाज कराने के तीन दिन पहले से लेकर भर्ती होने तक और छुट्टी होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव 15 दिन तक का सारा इलाज इतना निशुल्क होता है कि आप अपनी खाली जेब लेकर जाएंगे और इलाज कराकर चुपचाप

वापस चले आएंगे, आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और क्या खूबी है? इस 'आयुष्मान भारत' का हिस्सा होने के लिए मैंने आपको जिन देशों के नाम बताए, इन सारी इंश्यारेंस स्कीम्स का लाभ लेने के लिए आपको हेफ्टी-हेफ्टी टैक्स देने पड़ते हैं। यह भारत की एक ऐसी स्कीम है, दुनिया की अजूबी स्कीम है। मैं उस दिन मोदीनॉमिक्स की बात कर रहा था और लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। यही मोदीनॉमिक्स है। एक नया पैसा जमा नहीं करना पड़ता है - पांच लाख तक का प्रति वर्ष। अभी परसों हमारे किसी सदस्य ने 'आयुष्मान भारत' के बारे में पूछा था। मैडम, इस साल 2 करोड़ 26 लाख परिवारों ने 'आयुष्मान भारत' स्कीम का लाभ ले लिया। हमारे पास एक स्कीम है, जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हम इसको दलीय सीमा से नहीं बांधेंगे। हम यह भी नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने इतनी बढ़िया सुविधा दी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसके पहले कोई सुविधा नहीं देता था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ऐसा कहना शायद अपने देश के साथ अन्याय हो जाएगा। सच क्या है? अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की रिपोर्ट 2021 में आई। दूसरा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 की रिपोर्ट 2015-16 में आई थी, यानी दोनों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 की रिपोर्ट्स का अंतर देखें, तो इनके अंतर से हमें मालूम हो जाएगा कि 2015 से लेकर 2021 तक की इस यात्रा में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में और लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। मनोज जी जानते होंगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सरकार नहीं कराती है। इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पापुलेशन साइंसेस, मुंबई की एक संस्था है, वह कराती है। वह पूरी तरह स्वायत्त संस्था होती है। उतनी ही स्वायत्त होती है, जैसा आप अकसर शिक्षा का जिक्र करते होंगे, तो 'प्रथम' और ASER की रिपोर्ट्स की चर्चा करते होंगे। जब हम लोग कभी शिक्षा पर बहस करेंगे, तो उस पर आएंगे। आज स्थिति यह है कि एक जमाने में जब हम लोग बच्चे थे, तब ढेर सारे ऐसे लोग होते थे, जिनके चेहरों पर छाले-छाले होते थे। उस समय डर लगता था कि कैसा आदमी है, जिसका सारा चेहरा फटा रहता था। आज हम एक भी आदमी ऐसा नहीं देखते हैं कि जिसके चेहरे पर छाले हों। वर्ष 1976 में हम लोगों ने स्मॉलपॉक्स को खत्म कर दिया था। उस समय जब खत्म किया, तब भी इस देश में राइट टू हेल्थ नहीं था। जब इसको खत्म किया, तब भी जीडीपी की तुलना में अकसर ये बहसें होती थीं कि हम स्वास्थ्य पर कम खर्चा करते हैं। यह सच है कि हमारा स्वास्थ्य पर औसत खर्च 1.29 परसेंट ऑफ जीडीपी है। यह सच है, लेकिन इसी स्वास्थ्य के खर्चे से और बिना राइट टू हेल्थ के हम लोगों ने स्मालपॉक्स को इरैडिकेट कर दिया। न जाने ऐसे कितने लोग होते थे, जो विकलांग होते थे। एक पैर से, एक हाथ से लूले होते थे, एक आंख से अंधे होते थे, उनका एक कान खराब हो जाता था, मुंह टेढ़ा हो जाता था। मैं बच्चों का डॉक्टर हूं। हम लोग उन बच्चों को देखते थे। मेरे अपने जीवन में पोलियो के बहुत सारे मरीज़ आए हैं। आज पोलियो कहां है? मनोज जी, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते थे, जो पैदा होते थे और पैदा होते ही उनको झटका आने लगता था। इसको टेटनस धनुष्टंकार या धनुर्वात कहते थे। मां-बाप देखकर घबरा जाते थे कि हमारा बच्चा कल ही पैदा हुआ है और आज क्या हो गया? आज धनुष्टंकार कहां है? टेटनस नाम की बीमारी को खत्म करने में जीडीपी परसेंटज की सीमा नहीं बनी, राइट टू हेल्थ की जरूरत नहीं पड़ी। एक जमाने में कुकुर खांसी नाम की बीमारी होती थी। आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे। जिसको हम पर्टुसिस कहते हैं, काली खांसी कहते हैं। आज वह काली खांसी कहां है? इस सदन में सबसे अधिक मैं ही खांसता हूं, उसके अलावा मैं

किसी को भी खांसते हुए नहीं देखता हूं। एक जमाने में हम लोग गलाघोंटू रोग देखते थे। बच्चों की सांस खिंच जाती थी, वे सांस नहीं ले पाते थे, जिससे वे घुटकर मर जाते थे। आज वह गलाघोंटू रोग कहां है? इसी देश में, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में लाखों बच्चे जैपनीज़ एन्सेफेलिटिस से मरते थे। आज क्या कोई जैपनीज़ एन्सेफेलिटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मर रहा है? ये सारी बीमारियां हम इसी जीडीपी की, इसी खर्चे की तुलना में, बिना स्वास्थ्य के अधिकार के जीत चुके हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं समझ सकता हूं, आप बोल नहीं रही हैं, लेकिन बोलना चाहती होंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : आप बोलिए। आज टाइम है। Chairman Sir has specifically sent a message that since we were not able to have the debate and today we have time, let it happen.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : अभी कोरोना हुआ। अमेरिका वाले लोग बड़ी कमाई करते हैं। अमेरिका में एक लाख पर 318 लोग मरे। माननीय मनोज जी, ब्राज़ील दुनिया का अकेला देश है, जहां आप कह सकते हैं कि साइंटिफिकली राइट टू हेल्थ है। मैं इसको स्वीकार करूंगा, क्योंकि वहां एक आदर्श यूनिवर्सल हेल्थकेयर है। यह सिर्फ वहां के नागरिकों के लिए नहीं है। अगर हम भी ब्राज़ील में टूरिस्ट बन कर चले जाएं और बीमार हो जाएं, तो हमारे लिए भी ब्राज़ील की सरकार पूरे निशुल्क इलाज़ की व्यवस्था करके, ठीक करके, तब हमें भारत वापस भेजेगी, लेकिन उस ब्राज़ील में क्या हुआ? कागज में तो हमने कहा कि वहां एक यूनिवर्सल हेल्थकेयर है, लेकिन ब्राज़ील में इसी कोरोना में, कोरोना के कारण एक लाख की जनसंख्या पर 315 लोग मरे। रूस में एक लाख की जनसंख्या पर 260 लोग मरे। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। इन आंकड़ों को आप भी देख सकते हैं। न तो आप कभी असत्य बोलते हैं और धीमे-धीमे आप मेरे बारे में समझ जाएंगे कि मैं सत्य के सिवाय कुछ बोलता ही नहीं हूं। यह आने वाले समय में मालूम हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**... मैडम, इस भारत में एक लाख में मरने वालों की संख्या 37 थी। यह है - मोदी इकोनॉमिक्स। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया के हैं। उन्होंने बड़ी स्वास्थ्य की सेवाओं की बेहतरी की है, बड़े अच्छे-अच्छे टर्शियरी हॉस्पिटल्स हैं, वे स्वास्थ्य पर बहुत सारा खर्च करते हैं। उनके एक लाख में 318 लोग मरते हैं और हमारे एक लाख में 37 लोग मरते हैं। स्वास्थ्य की सेवा, जीडीपी पर हम बातें तो करते हैं, जब स्वास्थ्य की बातें करते हैं, तो कहते हैं कि जीडीपी में स्वास्थ्य पर बड़ा खर्च होता है, कम खर्च होता है। जब कृषि पर बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जीडीपी पर -- आज सुबह ही प्रश्न आया था कि जीडीपी का कितना कृषि पर खर्च होता है, तो हम कहते हैं कि कृषि पर बड़ा कम खर्च होता है। जब डिफेंस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि डिफेंस पर बड़ा कम खर्च होता है। आखिर खर्च तो सौ रुपये में ही होना है। महत्व खर्च का नहीं है, महत्व खर्च के सदुपयोग का है। मैडम, यह 'आयुष्मान भारत योजना' लागू हुई। हमारी पार्टी का एक-एक विधायक और मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करूंगा, यह अधिकार तो इन लोगों का भी था, ये नहीं गए, यह इनकी समस्या है, it was open to all, हमारी पार्टी के एक-एक विधायक को कोटा दिया गया था। पर हम लोग कभी-कभी परेशान हो जाते हैं कि कितना काम करें, एक-एक अनूसूचित जाति के मोहल्लों में जाएंगे, जिनके नाम छूट गए होंगे, उनके नाम को

जुड़वाएंगे। आयुष्मान भारत की योजना की ईमानदारी कितनी थी? उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत की सूची बनी, Socio Economic Survey, 2011. उस Socio Economic Survey को जब 2011 में किया गया, तो सरकार भाजपा...(**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): One minute, please. Madam, time allotted for this Bill is two hours, and already two hours and twenty minutes have passed. How much more time will be given for this? Other Bills are also there. Some more Members have to speak. The Minister has to reply and then again the Member who has moved the Bill has to speak. Kindly consider. Two hours have been allotted and already two hours and twenty minutes have passed.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : मैडम मुझे बहुत अच्छा लगा। ...(**व्यवधान**)... प्लीज़, आप बैठिए।

SHRI TIRUCHI SIVA: I think it will take one more hour. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Chairman has suggested that the House is running after a very, very long time. *...(Interruptions)...* It is an important topic. So, let it happen. *...(Interruptions)...* That is why he has *...(Interruptions)...*There is only one more speaker, Tiruchi Siva ji.

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : ये स्वास्थ्य सेवाओं में भारत की उपलब्धि से दुखी हैं। ...(**व्यवधान**)... इनको सच सुनने की आदत ही नहीं है। मैं यह पहली बार देख रहा हूं कि यहां नीचे बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि इतना क्यों बुलवाया जा रहा है, यहां तो सब कहते हैं कि हमारी ही बातों को सुना जाए। इसलिए क्योंकि सत्य ऐसा ही होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है:-

"सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्
नासत्यं च प्रियं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः"।

असत्य भी मत बोलो। हम लोगों की सीमा यह है कि हमारी सत्य की उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं कि हम क्या कहें और क्या न कहें। फिर भी, चूंकि माननीय सदस्य ने आपत्ति दर्ज कराई है, मैं उनकी इस आपत्ति का सम्मान करूंगा। मैडम, मैं कुछ बातें कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा बोलने का तो बहुत मन था, लेकिन मुझे माननीय सदस्य का भी सम्मान करना है। ..(व्यवधान)..ठीक बात है, यदि कल ये वहाँ बैठ जाएंगे, तो क्या होगा? उनके साथ बनाकर रखना पड़ेगा। मैडम, हमारे यहाँ मेडिकल में टर्म्स आती हैं - infant mortality, under-five mortality, maternal mortality. मैडम, ये तीन ऐसे शब्द हैं, रेश्यो हैं, जो पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बताते हैं। मैडम, सच्चाई क्या है? हमारे यहाँ पर माना जाता है कि यदि कोई भी

गर्भवती महिला है, तो उसकी एंटीनेटल केयर करनी चाहिए। इस देश में 95 प्रतिशत महिलाएं युनिवर्सल एंटीनेटल केयर पाती हैं। मनोज जी, इस श्रेणी में 95 प्रतिशत महिलाएं हैं। मैडम, 59 परसेंट ऐसी हैं, जो स्वयं को कम से कम चार बार दिखलाती हैं। इन 95 परसेंट महिलाओं में से 85 परसेंट महिलाएं ऐसी हैं, जो क्वालिटी क्वालिफाइड स्किल्ड मेडिकल केयर पाती हैं, 97 परसेंट महिलाएं ऐसी हैं, जिनका वजन होता है, 96 परसेंट महिलाएं ऐसी हैं, जिनका ब्लड प्रेशर लिया जाता है और 94 परसेंट महिलाएं ऐसी हैं, जिनके खून की और पेशाब की जाँच की जाती है। मैडम, आप मुझे बताइए कि दुनिया के इतने सारे देश, उनकी इतनी आय, इतनी सारी खपत और एक भारत, जो इतना कम खर्च करता है, उसके लिए मैं गारंटी से कह रहा हूं, यह फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है कि इतनी सारी गर्भवती महिलाओं को हम यह सुख देते हैं। मैडम, सच क्या है? सच यह है कि आज इस देश में 94 परसेंट इंस्टिट्यूशनल, संस्थागत डिलीवरी हो रही है। उपसभाध्यक्ष महोदया, हम फैमिली प्लानिंग की स्कीम चलाते हैं, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जो महिलाएँ अस्पतालों में आकर डिलीवरी कराती हैं, हम उनको 1,600 रुपये ईनाम में भी देते हैं। मैडम, दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं होता होगा। देहात की महिलाओं को 1,600 रुपये और शहर की महिलाओं को 1,000 रुपये 'जननी सुरक्षा योजना' के तहत दिए जाते हैं। उसका फल क्या हुआ है? मैडम, जब यह देश आज़ाद हुआ, तो हमारे 1 साल के 1,000 बच्चों में से 190 बच्चे मर जाते थे, लेकिन आज 1,000 में से सिर्फ 28 बच्चे मरते हैं। कहाँ 190 और कहाँ 28, और वह भी बिना किसी राइट टू हेल्थ के और बिना किसी अतिरिक्त स्वास्थ्य के खर्च के! हमारे 5 वर्ष से कम के बच्चों में 1,000 में से 250, यानी 25 परसेंट बच्चे 5 वर्ष की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते मर जाते थे, लेकिन आज इनकी मौत की संख्या सिर्फ 39 है। ये जो मौतें घटी हैं, ये इसी जीडीपी के खर्चे में से घटी हैं और बिना राइट टू हेल्थ के घटी हैं। जब हमारी माताएं गर्भवती होती थीं, तो 370 महिलाएं गर्भधारण के दौरान मर जाती थीं, लेकिन आज ऐसी दुखद मौत पाने वालों की संख्या 370 से घटकर 103 हो गई है। महोदया, यह है भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्धि। यह सिर्फ इसलिए है, क्योंकि हमने इसको सुनिश्चित किया है।

मैडम, एक ज़माने में कहा जाता था कि एक रुपया चलता है, तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन आज हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर यहाँ से एक रुपया चलता है, तो पूरा एक रुपया नीचे पहुंचता है, बीच में कहीं पर भी गायब नहीं होता है। इसका फल क्या निकला? उपसभाध्यक्ष महोदया, ये आंकड़े हैं कि जब देश आज़ाद हुआ, तो हमारे 1,000 में से 28 लोग मरते थे, जिसको हम लोग क्रूड डेथ रेट कहते हैं। आज यह क्रूड डेथ रेट घटकर 7.5 हो गया है, यानी 75 परसेंट मौतों को हमने इसी स्वास्थ्य सेवा के सहारे रोक लिया है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, जब यह देश आज़ाद हुआ, तो देश का औसत नागरिक 34 साल तक जीता था। हम कहते जरूर हैं कि यहाँ के लोगों की उम्र बहुत अधिक होती थी, लेकिन मनोज जी, आंकड़े इसी बात के गवाह है कि इस देश में सन् 1950 में व्यक्ति 34 साल की औसत आयु जीता था, लेकिन आज व्यक्ति 70 साल की औसत आयु जीता है, लगभग 69.79 वर्ष। हमने अपनी आयु को इसी जीडीपी के खर्चे से और इसी राइट टू हेल्थ से इतना अधिक बढ़ा लिया है। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

अभी केरल से हमारे एक मित्र श्री संदोष कुमार पी बैठे थे, अभी भी बैठे हैं, ये भी मेरे मित्र हैं, संदोष जी सब समझते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केरल की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। अमर्त्य सेन

ने कभी लिखा था कि उत्तर प्रदेश में एक बच्चा पैदा होता है और केरल में एक बच्चा पैदा होता है तो दोनों के जीने की संभावना में 6 गुना का अंतर होता है। यह केरल की एक सच्चाई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि...(**व्यवधान**)...आप जान रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं। केरल की एक सच्चाई थी कि वहां लिंग रेश्यो 1,000 के मुकाबले में 1,047 होता था। मुझे आश्चर्य होता है कि आप खड़े होकर राइट टू हेल्थ को सपोर्ट कर रहे थे तो आप शायद केरल का अपमान कर रहे थे। क्यों? केरल ने स्वास्थ्य की यह ऐतिहासिक सफलता क्या राइट टू हेल्थ से पाई है? केरल में राइट टू हेल्थ नहीं है और केरल ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी से यह ऐतिहासिक सफलता पाई है। इससे यह सिद्ध होता है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हमें राइट टू हेल्थ की नहीं, एक रुपये को चलाकर के एक रुपये को नीचे पहुंचाने की जरूरत है, जो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।

SHRI TIRUCHI SIVA: Excuse me, Madam Vice-Chairman. Actually, time allotted was 46 minutes. He spoke for 31 minutes. Now, the clock is showing the remaining time as 23 minutes. Already, Dr. Anil Agrawal spoke for a few minutes. So, what is the time left in the clock?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Members, a lot of Members are not in the House today. Therefore, we are extending the time.

SHRI TIRUCHI SIVA: I am talking only about the clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): In fact, unfortunately, अग्रवाल जी का मुझे टाइम बन्द करना पड़ा। Okay. Let us now hear Dr. Ashok Bajpai.

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : माननीय महोदया, अभी डा. राधा मोहन जी ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विस्तार से चर्चा की है। इस देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति यह देश और देश की सरकार कितनी चिन्तित रही है, इससे आज देश का बच्चा-बच्चा परिचित है। हम राइट टू हेल्थ, केवल एक संवैधानिक शब्द को अगर छोड़ दें तो जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की सुरक्षा की गारंटी सरकार ने ली है और आम जन को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिल सकें, इस पर गम्भीरता से चिन्ता करने का काम किया है, महोदया, आप स्वयं इससे परिचित होंगी। पहले हमारे पास मेडिकल डाक्टर्स की कितनी कमी थी कि हम चाहते हुए भी आम जन को मेडिकल की सुविधाएं नहीं दे पाते थे। एक लाख की आबादी पर हमें कितने चिकित्सक चाहिए थे, वह हम नहीं दे पाते थे, लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने बड़े पैमाने पर प्रत्येक जनपद में मेडिकल कालेज खोलने का संकल्प लिया है। आज देश के लगभग अधिकांश जिलों में नये मेडिकल कालेजों की स्थापना हो रही है। इन मेडिकल कालेजों से जो हमारे डाक्टर स्नातक बनकर निकलेंगे, इनकी सेवाएं हमारे आम जन को मिल सकेंगी और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं इन डाक्टरों के माध्यम से, चिकित्सकों

के माध्यम से हम आम जन तक पहुंचाने का काम कर सकेंगे। अभी तक चाहे हमारे तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हों या हमारे दूसरे हेल्थ के सेंटर्स हों, हम उन पर पर्याप्त मात्रा में चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं करा पाते थे, क्योंकि बड़े पैमाने पर डाक्टरों की कमी थी, लेकिन आज अभियान चलाकर पूरे देश में नये चिकित्सकों को तैयार करके हम उस कमी को पूरा करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 वर्षों में यह कमी पूरे देश में दूर होगी। जनसंख्या के आधार पर जितने चिकित्सकों की आवश्यकता होगी, उन्हें हम उपलब्ध करा सकेंगे।

केवल स्वास्थ्य सुविधाओं से ही, केवल दवा से ही इलाज करने का लक्ष्य हमारी सरकार का नहीं रहा है। हम ऐसा वातावरण सृजित करें, जिससे कि देश का स्वास्थ्य अच्छा रहे। सबसे पहले हमारी सरकार ने स्वच्छता मिशन को चलाने का काम किया है और हमने सैनिटेशन पर जोर दिया है। जब समाज स्वस्थ होगा तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। उसके लिए स्वच्छता का एक अभियान चलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैडम, आप जानती ही हैं कि इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा नये स्वच्छ शौचालय निर्मित कराकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में कितना बड़ा कार्य करने का काम किया गया है। जहां-जहां स्वच्छ शौचालय बने हैं, वहां स्वास्थ्य में एक गुणात्मक सुधार आया है, इससे सभी लोग अवगत हैं। इस तरह से हमने स्वच्छता अभियान चला कर भी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने का काम किया।

आज 'खेलो इंडिया' के माध्यम से हम नई पीढ़ी को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, जिससे जहाँ वे 'खेलो इंडिया' की प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेकर मेडल लेकर आएँगे, वहीं इससे खेलों में हमारे नौजवानों की अभिरुचि बढ़ेगी और स्वस्थ बच्चा निश्चित रूप से हमारे देश के विकास में अग्रणी होगा तथा हमें उसके स्वास्थ्य के लिए उतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से 'फिट इंडिया' का कार्यक्रम चला कर, ताकि हमारी नई पीढ़ी फिट रहे, स्वस्थ रहे, इस दिशा में भी सामाजिक वातावरण सृजित करने का काम किया गया। आज बड़े पैमाने पर जन-जन तक इन योजनाओं का लाभ पहुँचाने का काम किया जा रहा है।

मान्यवर, इसके साथ ही आप देखें, हमने जगह-जगह पर एम्स की स्थापना की। पहले एक एम्स पर कितना प्रेशर रहता था! देश के तमाम मरीज दिल्ली के एम्स के ऊपर निर्भर रहा करते थे। आज हमने हर प्रदेश में एम्स की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में तीन-तीन एम्स की स्थापना हो रही है। इस तरह से हमारी सरकार निरंतर विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार करने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, आप स्वास्थ्य सेवाओं के जिन क्षेत्रों को देखें, उन क्षेत्रों में आज इसके अच्छे परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं।

मान्यवर, हमने हर घर को नल से जल पहुँचाने का संकल्प लिया है। शुद्ध जल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा कारण है। हम अभी तक लोगों को स्वच्छ जल नहीं दे पाते थे, शुद्ध जल नहीं दे पाते थे। लेकिन मोदी जी ने संकल्प लिया कि हम हर घर नल से जल पहुँचाने का काम करेंगे। जब स्वच्छ जल पीने को मिलेगा, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस तरह से विभिन्न प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। केवल यही नहीं कि हमने मेडिकल बजट को बढ़ाया, बल्कि हमने उन तमाम आयामों पर ध्यान देने का काम किया, जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। जब पर्यावरण अच्छा रहेगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होगा, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य पर भी उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख कर हमने बड़े पैमाने पर हरित क्रांति को प्रारम्भ किया है, ताकि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण

करके हम देश के पर्यावरण को भी सुधारने का काम कर सकें। हम नदियों के जल को स्वच्छ करने का काम करेंगे, ताकि पीने वाला जल स्वच्छ हो, शुद्ध हो, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर उसका अनुकूल प्रभाव पड़े। बहुत सी बीमारियाँ गंदा पानी पीने से हो जाया करती थीं। उन बीमारियों का इलाज इस स्वच्छ जल से होगा। हमने नल से जल पहुँचाने का जो संकल्प लिया है, उसके पीछे यह बड़ा उद्देश्य है। इससे लोगों के स्वास्थ्य में एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आएगा और उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा।

इसी तरह से विभिन्न रूपों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए हमने गर्भवती महिलाओं के लिए 'पोषण योजना' का कार्यक्रम प्रारम्भ किया। 'पोषण योजना' यह योजना है कि गर्भवती महिलाओं को अच्छा और शुद्ध भोजन मिले, इसके साथ-साथ उनको नरिशमेंट वाली डाइट मिले, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके और उत्पन्न होने वाले बच्चे का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस 'पोषण योजना' के माध्यम से उन तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम किया गया है, जिनसे हमारी गर्भवती माताओं की मेडिकल डॉक्टर की जाँच समय-समय पर हो। लगातार तीन महीने पहले से ही हॉस्पिटल से उनको लिंक करके, ताकि समय-समय पर उनका चेक-अप हो और डिलीवरी के बाद भी आने वाले एक-दो महीने तक उनकी देख-रेख करने का काम हो। इससे हमारा मॉर्टिलिटी रेट भी सुधरा है, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ है और हमारी गर्भवती माताएँ-बहनें स्वस्थ रही हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में हमने केवल स्वास्थ्य विभाग का बजट ही नहीं बढ़ाया, बल्कि हमने इसके साथ-साथ जो सारे पैरामीटर्स हैं, जिनसे स्वास्थ्य सुविधाएँ अच्छी हो सकती थीं, उन सब पर ध्यान देने का काम किया।

मान्यवर, इसी तरह से हमारी जेनेरिक मेडिसिन्स हैं। अभी तक आम आदमी महँगी दवाएँ नहीं खरीद पाता था। जेनेरिक मेडिसिन्स के माध्यम से हमने जगह-जगह जेनेरिक मेडिसिन्स स्टोर्स खोले हैं, जिनसे सस्ती दवाएँ मिलती हैं। बहुत सी दवाएँ ऐसी हैं, जिनकी कीमत 50 प्रतिशत से भी कम है। ये दवाएँ गरीब आदमी के लिए एफोर्डेबल हैं। उन दवाओं को बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में चिह्नित करके हमने उन्हें जेनेरिक मेडिसिन्स स्टोर्स में उपलब्ध कराने का काम किया है, ताकि लोगों का सस्ता इलाज हो सके।

मान्यवर, अभी 'आयुष्मान योजना' का ज़िक्र हो रहा था। 'आयुष्मान योजना' के अंतर्गत अभी लगभग 18 करोड़ लोगों के काड्र्स बन चुके हैं। अगर हम एक परिवार में पाँच लोगों का भी औसत रखें, तो 80-90 करोड़ लोग 'आयुष्मान योजना' से जुड़ चुके हैं। यह योजना ऐसी है, जिससे हर गरीब को अपने गम्भीर मर्ज़ के इलाज के लिए अब किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, किसी गरीब को अपना खेत गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, उसे किसी साहूकार से कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। यह 'प्रधान मंत्री आयुष्मान योजना' का कार्ड एक ऐसा कार्ड है, जिससे उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को जब कभी ऐसी गम्भीर बीमारी होगी, उसका 5 लाख तक का इलाज हो सकेगा। कल्पना करिए, माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के आने से पहले अगर किसी गरीब को कोई गम्भीर मर्ज़ हो जाता था, चाहे हृदय का रोग हो, किडनी का रोग हो, लीवर का रोग हो या कैंसर की बीमारी हो, तो इन गम्भीर बीमारियों का इलाज एक गरीब आदमी नहीं करा पाता था। अगर कोई हिम्मत कर भी लेता था, तो वह अपनी आजीविका की सारी खेती-पाती बेच कर कहीं इलाज की बात सोचता था। लेकिन प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना का कार्ड बनाकर हर

गरीब को यह अधिकार देने का काम किया है और उनमें यह विश्वास जगाया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का भी अच्छे से अच्छा इलाज हो सकता है। आज लोग बड़े पैमाने पर आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमसे पूर्व डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि मरीज खाली हाथ जाता है, अस्पताल में भर्ती होता है, पूरा इलाज कराता है और इलाज कराने के बाद बिना एक पैसा खर्च किए, स्वस्थ होकर घर लौट आता है। यह आयुष्मान योजना के कारण सम्भव हुआ है।

मैडम, हमारी सरकार का संकल्प है कि हम जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छे से पहुंचाने का काम करेंगे और उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर लाभान्वित करने का काम करेंगे। जैसा मैंने अभी कहा, राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत हमने डेफिशियेंसी अमंग चिल्ड्रन को दूर करने का काम किया है। प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के माध्यम से भी हमने लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने की दिशा में बढ़-चढ़ कर काम किया है। इसी तरह से प्रधान मंत्री जन-आरोग्य योजना, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया था, इसके माध्यम से भी जन-जन को अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की दिशा में हमने काम किया है। इस योजना में 2022-23 के बजट में हमने 30,673 करोड़ रुपये रखे हैं।

मैडम, इतना ही नहीं, अगर हम स्वास्थ्य विभाग के बजट को देखें, तो जब से मोदी जी की सरकार बनी है, हर वर्ष स्वास्थ्य विभाग के बजट में बढ़ोतरी हुई है। यद्यपि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है, लेकिन भारत सरकार ने लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की ओर गम्भीरता से ध्यान दिया है। कोविड जैसी महामारी में, जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी घुटनों के बल आ गई थीं, ऐसे समय में हमारे प्रधान मंत्री जी ने देश की 130 करोड़ आबादी के लिए, एक ओर कोविड की बीमारी से मुक्ति दिलाने में बढ़-चढ़ कर काम किया, उनको मुफ्त इलाज देने का काम किया और दूसरी ओर 80 करोड़ परिवारों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने का काम भी किया। दो वर्ष तक लगातार यह कार्यक्रम चलता रहा है, जिससे उन गरीबों को, जिनकी रोज़ी-रोटी चली गई थी, जिनकी नौकरियां चली गई थीं, जिनके छोटे-मोटे व्यापार ठप हो गए थे, उन सबको इस योजना से जोड़ कर निशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम किया। आज भारत में कोविड रोधी वैक्सीन की 200 करोड़ डोज़ेज़ लग चुकी हैं और प्रधान मंत्री जी का देश की जनता के नाम रोज़ यह निवेदन आता है कि आप बूस्टर डोज़ ज़रूर लगवाएं। इस तरह मैं समझता हूं कि यह दुनिया की पहली ऐसी सरकार होगी, जिसने इतने बड़े पैमाने पर अपने लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, निशुल्क वैक्सीनेशन कराने का काम किया है, साथ ही वह लगातार उसे और आगे बढ़ाने का काम कर रही है।

मैडम, हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। देश को टीबी से मुक्ति दिलाने की दिशा में हमारी सरकार बढ़-चढ़ कर काम कर रही है। जल्दी ही हम अपने देश को क्षय रोग से मुक्त कराने का काम करेंगे, उस दिशा में बड़े पैमाने पर कार्य योजना बनी है। मैं समझता हूं कि 2025 तक हमारे देश को क्षय रोग से मुक्ति मिल जाएगी। जिस तरह से हमारे देश के चिकित्सकों ने और देश के लोगों ने मिल कर पोलियो से मुक्ति दिलाने का अभियान चलाया था, साथ ही तमाम ऐसी अजीर्ण बीमारियों से मुक्ति दिलाने का काम किया था, उसी तरीके से हम देश को क्षय रोग से भी मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने का काम कर रही है।

मैडम, हम केवल ऐलोपैथी पर ही निर्भर नहीं हैं। हम एक नौजवान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से, योग के माध्यम से हमारे देश में लगातार इस कार्य को किया जा रहा है। आज भारत के योग दिवस को पूरी दुनिया ने स्वीकारा है। योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं और लम्बे समय तक जीवित भी रह सकते हैं। योग को लेकर हमारे ऋषियों-मुनियों ने जिस परम्परा की शुरुआत की थी, जिससे वे सैकड़ों सालों तक जीवित रहते थे, उस योग को पुनर्स्थापित करने की दिशा में देश के प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। आज पूरी दुनिया योग को अपनाने के लिए बाध्य हो गई है, उस योग को हम आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हम सभी स्वस्थ रह सकेंगे।

मैडम, चाहे सिद्ध हो, चाहे आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो, ऐसी तमाम जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां थी, उनको भी आगे बढ़ाने की दिशा में काम हुआ है। भारतीय चिकित्सा पद्धति पर आज बड़े पैमाने पर शोध और अनुसंधान हो रहे हैं। अब इन दवाओं के माध्यम से तमाम अजीर्ण रोगों का इलाज भी संभव हो सकेगा। अभी तक इन भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में शोध की दिशा में काफी कम काम हुआ था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, तब से तमाम आयुष दवाओं के ऊपर बड़े पैमाने पर शोध चल रहा है। हमारे जंगलों में, पहाड़ों में ऐसी-ऐसी चमत्कारिक जड़ी-बूटियां हैं, जिनमें से एक जड़ी-बूटी देकर लक्ष्मण जी को भी मूर्छा से मुक्ति दिलाई गई थी। संजीवनी जैसी बूटी को हम लोग खोजने में कामयाब रहे थे। हमारी सरकार ऐसी-ऐसी बूटियां खोज रही है, जो गम्भीर रोगों के उपचार में काम आएंगी, उन बूटियों को खोजने और उन पर शोध और अनुसंधान करने की दिशा में बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। आज हमने तीन ऐसे विश्वविद्यालयों, शोध केन्द्रों की स्थापना की है, जहां बड़े पैमाने पर हमारी आयुष दवाओं के ऊपर शोध और अध्ययन हो सके। इस तरह से अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, तो जिस तेजी के साथ और जिस चिंता के साथ काम हो रहा है, सरकारों के सरोकारों से आप देखेंगे कि आज देश की सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार कितनी चिंतित है और वह चिंता केवल हमारे भाषणों तक ही सीमित नहीं है, हम उसे व्यावहारिक रूप में भी साकार कर रहे हैं। हमारे देश के कर्मठ स्वास्थ्य मंत्री ने जिस तरह से कोविड-19 की महामारी में रात-दिन काम करके देश को स्वस्थ करने का काम किया और आफ्टर कोविड-19 सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए, वह कम है।

माननीय मनोज झा जी ने जिस उद्देश्य से इस विधेयक को लाने का काम किया है, मैं उनसे आग्रह करूंगा, वे एक विद्वान व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने हमारी सरकार के इन कामों पर एक बार गम्भीरता से नजर डाली होती, तो शायद उन्हें यह विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होती। हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारे देश का जन-जन स्वस्थ रहे, हम लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें, स्वास्थ्य हमारी जनता के लिए एक वरदान है। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता इस सरकार ने हर रूप में की है, इसलिए इसको हम निश्चित रूप से इसको आगे विस्तार देने का काम कर रहे हैं और हम सदन को भी विश्वास दिलाना चाहेंगे कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार इस देश के 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करती है और उनको स्वस्थ रखने के लिए हर प्रयास करती है। क्योंकि जब देश स्वस्थ होगा, तभी हम विकास की ओर आगे जा सकेंगे। जो हमारी संकल्पना है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, वह तभी बनेगा,

जब हमारा मन स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, हम पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, तभी हम देश को आगे ले जाने का काम करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं डा. मनोज झा जी से कहना चाहूंगा कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं हैं, चूंकि जो आपकी अपेक्षाएं हैं, वे हमारी सरकार पूरी कर रही है और उन सारे पैरामीटर्स पर हमारी सरकार खरी उतरी है, इसलिए इस विधेयक को लाने का कोई विशेष औचित्य नहीं है। मैं फिर से आग्रह करूंगा कि इस विधेयक पर विस्तार से सारी बातें सामने आई हैं और आप स्वयं एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसलिए इस विधेयक पर आगे दबाव देने की आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद।

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सदन के सदस्य, माननीय मनोज झा जी ने जो प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया है, देखने और सुनने में वह बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन व्यावहारिक कसौटी पर यदि हम इस प्रस्ताव को कसते हैं, तो प्रस्ताव बहुत सामयिक नहीं लगता है। यह बात सही है कि स्वस्थ शरीर को हमारी संस्कृति में, हमारे अध्यात्म में हमेशा प्राथमिकता दी गई है और इसीलिए कहा गया है - 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्'। धर्म साधना का माध्यम शरीर है, इसलिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। यह भी कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही ईश्वर का वास होता है।

महोदया, मैंने एक प्रसंग में पढ़ा है कि एक किशोर स्वामी विवेकानंद जी के पास जाता है और उनसे आध्यात्म जानने और सीखने की इच्छा प्रकट करता है। स्वामी विवेकानंद उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हैं। वह नौजवान कहने के लिए नौजवान था, परंतु वास्तव में वह हड्डियों का ढांचा था। उस नौजवान को उन्होंने सीख देते हुए कहा कि अभी तुम्हारा शरीर आध्यात्म जानने और सीखने लायक नहीं है। सामने मैदान में जो बच्चे फुटबाल खेल रहे हैं, तुम उनके साथ जाकर फुटबाल खेलो, अपने शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाओ और जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तब तुम अध्यात्म को अच्छी तरह से जान भी पाओगे और सीख भी पाओगे। इसलिए शरीर के महत्व को तो हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन जो देश की वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो स्वास्थ्य का अधिकार विषय यहां मनोज जी प्रस्तुत कर रहे हैं, उस विषय की मैं बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं समझता हूं। हमारे साथी मनोज जी इस प्रस्ताव के माध्यम से जिस समाज की रचना की कल्पना कर रहे हैं, जिस समाजवादी समाज की रचना की कल्पना कर रहे हैं, अगर हम दुनिया पर दृष्टिपात करें, तो यह समाजवादी विचार पूरे तरीके से फेल हो गया है। दुनिया के अगुआ देश, जो समाजवाद की अगुवाई किया करते थे, आज भी वे केवल नाम मात्र के समाजवादी रह गए हैं। कृत रूप में, विचार रूप में उनमें भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है।...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN)**:** No comments please.

श्री अजय प्रताप सिंह : जब हम लोग छोटे-छोटे थे, तो अपने समाजवादी मित्रों का नारा सुना करते थे कि धन और धरती बँट कर रहेगी, भूखी जनता अब ना रहेगी, लेकिन व्यवहार रूप में

देखें, तो जैसे अभी हमारे बुजुर्ग साथी कह रहे थे कि धन और धरती तो नहीं बँटी और उनका समाजवाद उनके परिवार तक ही सीमित रह गया। उसी तरीके से यह विषय भी है। यह विषय भी व्यावहारिक धरातल पर खरा नहीं उतरेगा। मैंने अपने मित्र अनिल जी को भी सुना, उन्होंने भी बहुत व्यावहारिक बात कही है कि हमारा भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश के साथ-साथ एक बहुत बड़ी आबादी है। अगर हम इन दोनों परिस्थितियों की विवेचना करें, तो आज की परिस्थिति में हमारी कुछ सीमाएँ हैं। केवल अधिकार देने भर से नहीं होता है, अगर हम कानून बनाते हैं, अधिकार देते हैं, तो हमें उसे लागू भी करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, तभी हमारी सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है, वह कायम रहती है, हमारी व्यवस्था की क्रेडिबिलिटी कायम रहती है। हमने अधिकार दे दिया, कानून बना दिया, लेकिन अगर वह व्यवहार रूप में क्रियान्वित नहीं हो रहा है, तो हमारा जो यह डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वह भी अपनी क्रेडिबिलिटी खोएगा और हमारी सरकार भी अपनी साख खोएगी, इसलिए हमें व्यावहारिक धरातल पर हर चीज को मोल-तोल करके व्यावहारिक कसौटी पर परख कर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए।

यह ठीक है कि हम स्वास्थ्य के अधिकार के संदर्भ में कानून बनाने के पक्ष में भले न हों, लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं का मामला है, देश के स्वास्थ्य का मामला है, तो इसके लिए मोदी सरकार हमेशा से गंभीर रही है। हम स्वास्थ्य के अधिकार को स्वीकार भले न करते हों, लेकिन हमने उन क्षेत्रों की पहचान करने की कोशिश की, उन क्षेत्रों की कमियों को दूर करने की कोशिश की है, जिनके कारण हमारे देश का स्वास्थ्य, हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उन कमियों को पहचान करके उनका निराकरण भी दिया है, उनका समाधान भी दिया है। मैं उसकी ओर अपने साथियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जब बच्चा गर्भ में आता है, तो कमजोर शरीर के कारण बहुत सारी माताओं का गर्भपात हो जाता था। समुचित देख-रेख के अभाव में बहुत सारी माताओं का जो गर्भधारण का समय है, वह कुशलतापूर्वक नहीं गुजरता था। मोदी सरकार ने आज पूरे देश में आशा कार्यकर्ताओं का एक संजाल खड़ा किया हुआ है। हर गाँव में दो, तीन या चार आशा कार्यकर्ताएँ नियुक्त हैं, जो गाँव की एक-एक गर्भवती बहन, एक-एक गर्भवती माता का लेखा-जोखा रखती हैं, उनके समय की जानकारी रखती हैं। उनको जो भी औषधि चाहिए, जो भी दवाइयाँ चाहिए, वे समय-समय पर उनको उपलब्ध कराती हैं। हमारे हिन्दुस्तान में रक्त अल्पता के बहुत मामले आते हैं, वे उन्हें खून बढ़ाने वाली दवाइयाँ, आयरन की गोलियाँ, फॉलिक एसिड की गोलियाँ आदि मुहैया कराती हैं। इसके लिए आशा कार्यकर्ता बराबर केयर करती है।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY) *in the Chair*.]

केवल इतना ही नहीं, जब प्रसव का समय आता है, तब आशा कार्यकर्ता उसके साथ जाकर अस्पताल में तीन दिन रह कर उस प्रसववती बहन की सेवा करती है और प्रसव के उपरांत जब वह माता अपने घर में सकुशल आ जाती है, तब जाकर ही हमारी उस आशा कार्यकर्ता बहन को उसका जो मेहनताना है, उसका जो पुरस्कार है, वह प्राप्त होता है।

4.00 P.M.

हमने देखा है कि गर्भावस्था के कारण और प्रसव के अवसर पर जो मातृ मृत्यु दर थी, इसके कारण उसमें भारी गिरावट आई है। मैडम, 108 नंबर एंबुलेंस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। हमारे देश में पहले संस्थागत प्रसव बहुत कम था, लगभग 18-20 परसेंट से लेकर 25 परसेंट तक, इसे लेकर अलग-अलग प्रांतों की अलग-अलग स्थिति हो सकती है। हमारे डॉक्टर साहब ने केरल की प्रशंसा की। यह हो सकता है कि केरल में संस्थागत प्रसव कुछ बेहतर रहा हो, लेकिन अमूमन पूरे हिन्दुस्तान में संस्थागत प्रसव बहुत कम हुआ करता था। परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि माताएं अपने बच्चों को जन्म घर की किसी अंधेरी कोठरी में दिया करती थीं। उस अंधेरी कोठरी की जो स्थिति हुआ करती थी, वह कल्पना से परे थी। आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह बड़ी अस्वच्छ परिस्थिति हुआ करती थी। गाँव में कुशल दाई तक नहीं मिला करती थी। इस देख-रेख के अभाव में कई बार शिशु की मौत हो जाती थी, तो कई बार माता की मौत हो जाती थी। इस संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए आशा कार्यकर्ता के साथ-साथ एंबुलेंस नंबर 108 का भी प्रावधान किया गया। आज आप किसी भी कोने से 108 नंबर डायल करिये, एंबुलेंस आपके घर पर आएगी। वे उस प्रसववती माता को आशा कार्यकर्ता के साथ हॉस्पिटल तक ले जाती हैं, वहाँ पर कुशल डॉक्टरों की देख-रेख में, कुशल नर्सों की देख-रेख में उसका प्रसव होता है और इसके कारण मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भारी गिरावट आई है।

सर, हमारे डॉक्टर साहब ने आयुष्मान कार्ड की बहुत सारी श्रेणियों का उल्लेख किया है। वे श्रेणियाँ ऐसी हैं कि जब तक आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था नहीं हुई थी, जब तक मोदी सरकार देश में शासन करने के लिए आगे नही आई थीं, तब तक ऐसी परिस्थितियाँ थीं कि आज प्रसव हुआ है और तीसरे दिन वह मजदूर माता माथे पर पट्टी बांधकर काम पर चली जाती थी। वह दिहाड़ी पर काम करने वाली माँ, वह सफाईकर्मी माँ, वह कमजोर वर्ग की माँ, जिसे रोज कमाना पड़ता है, रोज कुआं खोदकर पानी पीना पड़ता है, वह इंतजार नहीं कर सकती थी, उसे तीसरे दिन ही काम करने के लिए काम करने के स्थान पर जाना पड़ता था। वह वहाँ अपने बच्चे को लेकर जाती थी, उसे साड़ी के पालने में झुला देती थी। मजदूर माताएं अपने बच्चों को झुला कर रख दिया करती थीं। यह उनकी मजबूरी थी। प्रसव के उपरांत, उन्हें जो पौष्टिक आहार चाहिए होता था, वह तो स्वप्न की बात हुआ करती थी, लेकिन आज सरकार के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। हम लोग अपनी बघेलखंडी में कहते हैं कि *"मोदी जी अपनी बहिनिन खातिर और अपनी बिटियन खातिर, प्रसव के उपरांत गुड़ और सौंठ खातिर पैसा भिजवाइन।"* अब उन मजदूर माताओं को काम करने की जरूरत नहीं है, उन्हें एक महीने की छुट्टी देने का प्रावधान है और यह प्रावधान केवल उन्हीं के लिए ही नहीं किया गया है, बल्कि उनके पति से भी कहा गया है कि हम तुम्हें भी 15 दिन की मजदूरी देंगे, तुम भी काम पर मत जाओ, तुम अपनी पत्नी की सेवा करो और यह सब स्वास्थ्य के अधिकार के कानून के बिना किया गया है।

मैडम, जब कोई बीमार होता था, तब महंगी दवाइयों का एक प्रसंग आता था। कई लोगों ने जेनरिक दवाइयों का जिक्र भी किया है। मोदी सरकार के आने से पहले जेनरिक दवाइयों के बारे में कौन जानता था। दवाइयों की महंगाई को लेकर चारों तरफ हाहाकार रहा करता था और अब

जेनरिक दवाइयों के माध्यम से इसका सॉल्युशन दिया है। सर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी उन्हीं स्टोर्स पर मिलते हैं, वे भी सस्ते हो गये हैं। इसमें जमीन-आसमान का अंतर हो गया है। अब दवाइयाँ आम आदमी की पहुंच से दूर नहीं हैं। अब सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं। आयुष्मान कार्ड के बारे में हमारे सभी मित्रों ने जिक्र किया है। आयुष्मान कार्ड ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज तो किसी प्रकार हो जाया करता था, लेकिन अगर किसी परिवार के किसी सदस्य को गंभीर बीमारी लग जाती थी, तो उस परिवार पर कहर टूट पड़ता था, हाहाकार मच जाता था। अगर परिवार के किसी सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी हो जाती थी, तो वह सदस्य तो इस दुनिया से जाता ही था, लेकिन उसके परिवार के जो अन्य लोग इस दुनिया में रह जाते थे, वे भी बरबाद हो जाते थे। उनकी जमीन बिक जाती थी, भड़वा-बर्तन बिक जाते थे, गहने-जेवर बिक जाते थे और ऐसी गंभीर बीमारियों के कारण अच्छे-खासे खुशहाल परिवार हाहाकार कर उठते थे। ...(**व्यवधान**)...

DR. V. SIVADASAN (Kerala): * I have an objection.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Under which rule?

DR. V. SIVADASAN: Sir, now the time is...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Are you raising a point of order?

DR. V. SIVADASAN: I have an objection.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): What is your objection?

DR. V. SIVADASAN: My objection is, he is making lengthy speeches. *That is why I am objecting.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): You cannot raise any objection on the decision of the Chair. Shri Ajay Pratap Singh, please continue.

श्री अजय प्रताप सिंह : सर, इस 'आयुष्मान कार्ड' के बारे में हमारे कुछ विपक्षी साथियों ने आलोचना करते हुए अनेक तरीके की बातें कही हैं। आज वे यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं सदन के माध्यम से उनसे यह कहना चाहता हूँ कि इस 'आयुष्मान कार्ड' के कारण कई परिवारों की जिंदगी बदली है। अगर वे 'आयुष्मान कार्ड' के प्रभाव को देखना चाहते हैं कि 'आयुष्मान कार्ड' के कारण परिवार आज किस हालात में पहुँचे हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ

* Not recorded.

कि वे मेरे गृह जिले में आएँ, मैं 1,000 आयुष्मान कार्डधारकों का सम्मेलन कराऊँगा और उनको उनसे मिलवाऊँगा, जिनको 'आयुष्मान कार्ड' के माध्यम से मदद मिली है और उनके परिवार के प्राणों की रक्षा हुई है। अगर इसको पूरे देश के पैमाने पर देखा जाए तो आज करोड़ों लोग मोदी जी को सच्चे दिल से दुआ देते हैं। यह कहा जाता है कि कई बार दवा से भी ज्यादा असर दुआ का होता है। आज मोदी सरकार की चारों तरफ जो वाहवाही हो रही है, मोदी जी को जो हर बात का श्रेय मिल रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि मोदी जी सब काम अच्छा कर रहे हैं, बल्कि उन अच्छे कामों के साथ-साथ मोदी जी के साथ करोड़ों लोगों की दुआ भी है, जिसके कारण मोदी जी को यह प्रेरणा मिलती है, उन्हें इस बात की ताकत मिलती है कि वे दुनिया में भारत का मान-सम्मान बढ़ाएँ, दुनिया में भारत का नाम रौशन करें।

महोदय, हमारे अनेक साथियों ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी चर्चा की। मैं भी उस बात पर बल देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य सेवाओं का जो इन्फ्रास्ट्रक्चर था, उस इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण मोदी जी के आने से पूर्व हम चाह कर भी अच्छी सेवाएँ नहीं दे सकते थे। जब डॉक्टर नहीं रहेंगे तो इलाज कैसे होगा? मोदी सरकार ने पहचान की कि यह वह क्षेत्र है, जिसकी कमी के कारण हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं, इसलिए उन्होंने तमाम मेडिकल कॉलेजेज़ खोले। मोदी जी का यह लक्ष्य है कि हर पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्युएंसी में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, how long will he speak? There are other Bills listed. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): You please sit down.

श्री अजय प्रताप सिंह : सर, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूरे देश में मेडिकल कॉलेज की शृंखला प्रारंभ की और इसका यह परिणाम हो रहा है कि आने वाले दिनों में हम प्रति वर्ष एक लाख से ऊपर नये डॉक्टर्स तैयार करेंगे। जो मरीज इलाज के लिए भर्ती होते हैं, उनकी सेवा करने के लिए जो नर्सिंग स्टाफ की आवश्यकता होती है, पहले उसकी कमी थी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी थी, पैथोलॉजी की कमी थी, टैस्टिंग की कमी थी। इन सारे क्षेत्रों में मोदी जी ने सुधार किया है, इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है, प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ाया है, अध्ययन केन्द्रों को बढ़ाया है, जिसका परिणाम है कि अब बड़ी तेजी से यह संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जो मानव संसाधन की कमी थी, उसकी पहचान करके मानव संसाधन को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह शनैः-शनैः पूर्ण हो रहा है और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होंगे। केवल मानव संसाधन ही नहीं, बल्कि पहले हॉस्पिटल्स की कमी थी, बेड्स की कमी थी। मोदी सरकार ने इसको भी पहचाना और हॉस्पिटल्स एवं बेड्स की कमी को पूरा करने के लिए केवल केन्द्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि उन्होंने राज्य सरकारों को भी जगह-जगह पर पर्याप्त संख्या में नये-नये हॉस्पिटल्स खोलने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम एम्स का तो उदाहरण देते ही हैं कि पहले एक एम्स हुआ करता था, अटल जी ने 1 से 6 एम्स किए और अब 6 से 22 एम्स हो रहे हैं। आने वाले दिनों में एम्स की संख्या यहीं पर रुकने वाली नहीं है, बल्कि वह

और बढ़ने वाली है। एम्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मानक है। अगर हमें क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए, तो वह कैसा चाहिए, उसका एम्स मानक है। अब 22 एम्स हो गए, यानी अब 22 ऐसे संस्थान हो गए, जो देशवासियों को क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। वे केवल क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो गंभीर बीमारियाँ हैं, उन गंभीर बीमारियों का सस्ता और अच्छा इलाज भी दे रहे हैं। यह पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले कभी इस पर विचार नहीं किया गया। लेकिन पहले कभी विचार नहीं किया गया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया और मानव संसाधन पर भी ध्यान दिया। इसके अतिरिक्त हमारे बाजपेयी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि अभी तक ज्यादातर चर्चा क्यूरेटिव मेज़र्स पर केंद्रित रही है कि व्यक्ति बीमार हो गया है तो उसका इलाज कैसे हो, इलाज करने के लिए क्या-क्या आवश्यकताएं हैं। प्रिवेंटिव मेज़र्स पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। मैं इस सदन का ध्यान प्रिवेंटिव मेज़र्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर बीमारी होती क्यों है। बीमारी जिसके कारण होती है, जहां होती है, उसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए। हमारे हिन्दुस्तान में एक बड़ी साधारण बात थी कि लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिलता था। यह सावन का महीना चल रहा है, आषाढ़, सावन और भादों के महीने में ग्रामीण क्षेत्रों में हैजा और कालरा जैसी बीमारी से 10-10, 15-15 मौतें होना स्वाभाविक बात थी। हमारे झा साहब भी इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे भी बिहार के हैं। ऐसी स्थिति बिहार में भी रही होगी, लेकिन कभी इस बात पर विचार नहीं किया गया कि पानी के कारण इतने बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, तो पानी को शुद्ध करना चाहिए, लोगों को शुद्ध पानी मिले। पानी के शुद्धिकरण से अगर लोगों की जान बचायी जा सकती है, तो इस व्यवस्था पर पहले क्यों ध्यान नहीं दिया गया? इसीलिए मोदी जी ने हर घर को नल से जल मिले, यह व्यवस्था लागू की है। वे बड़ी तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले दो-चार सालों के अंदर हिन्दुस्तान के प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचेगा। इसका अर्थ है कि हिन्दुस्तान के प्रत्येक घर को और प्रत्येक घर के प्रत्येक निवासी को शुद्ध और साफ जल पीने को मिलेगा और गंदे पानी के कारण जितनी बीमारियां होती थीं, उनको हम बड़े पैमाने पर रोकने में सफल होंगे। केवल इतना ही नहीं, मैं सड़क तक की बात कहना चाहता हूं। अटल जी ने 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' लागू की और मोदी जी ने उस क्रम को आगे बढ़ाया और हिन्दुस्तान के सुदूर गाँवों को 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' से जोड़ दिया। लोग कहेंगे कि यहां स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है, मैं सड़क की बात कर रहा हूं, इसलिए बात कर रहा हूं कि आप लोगों ने भी अखबारों में चित्र देखे होंगे, आप लोगों को भी अनुभव होगा कि पहले जहां सड़कें नहीं हुआ करती थीं, अगर वहां कोई बीमार हो जाता था, तो मरीज़ को डोली और खटोली में लाद कर अस्पताल पहुंचाया जाता था। अगर इस मौसम में कोई प्रसववती बहन है, तो उसको किस तरह से अस्पताल तक पहुंचाया जाए, यह एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, लेकिन आज 'प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना' के माध्यम से अस्पताल आसानी से पहुंच जाती हैं। इसके अतिरिक्त 108 नम्बर पर एम्बुलेंस भी मिलती है, अगर एम्बुलेंस किसी कारण नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो लोगों के पास अपने संसाधन हैं, वे उस संसाधन के माध्यम से 5-10 मिनट के अंदर ...(**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, what is this? ...*(Interruptions)*... How long will he speak? ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, what is this? *...(Interruptions)...* *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Sit down, please. *...(Interruptions)...*

SHRI TIRUCHI SIVA: * *...(Interruptions)...*

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): * *...(Interruptions)...*

SHRI TIRUCHI SIVA: * *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please sit down. *...(Interruptions)...*

SHRI TIRUCHI SIVA: There should be some limit. *...(Interruptions)...*

श्री अजय प्रताप सिंह : इन सड़कों के कारण आज बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज करने के लिए मरीज़ को अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। 'सौभाग्य योजना' के तहत हर घर में बिजली पहुंचा दी गई है।

SHRI M. MOHAMED ABDULLA: Sir, there are also other Bills. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please sit down. *...(Interruptions)...*

DR. JOHN BRITTAS: Sir, I am on a point of order. *...(Interruptions)...*Sir, I am on a point of order. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Under which rule?

DR. JOHN BRITTAS: I am telling you. *...(Interruptions)...*
THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Tell me the rule.

SHRI TIRUCHI SIVA: There is a limit for everything. *...(Interruptions)...*

---

* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): He has a point of order. *...(Interruptions)...*

Dr. JOHN BRITTAS: Sir, Rule 258. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Rule 258 is a general rule. *...(Interruptions)...* No, no. *...(Interruptions)...*

DR. JOHN BRITTAS: Sir, please allow me. *...(Interruptions)...* # Private Member's Business has not come. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Listen to me. Listen to me. *...(Interruptions)...*

DR. JOHN BRITTAS: Today, my colleague's Bill is to come up now. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Listen to me. *...(Interruptions)...*

DR. JOHN BRITTAS: * *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): You have mentioned a wrong rule. *...(Interruptions)...* You have mentioned a wrong rule. Listen to me. *...(Interruptions)...*Listen to me. *...(Interruptions)...*This is wrong rule. *...(Interruptions)...*Nothing will go on record. *...(Interruptions)...*Nothing will go on record. *...(Interruptions)...* Nothing will go on record. *...(Interruptions)...* It is a wrong rule mentioned by him. *...(Interruptions)...*

DR. JOHN BRITTAS: *

SHRI TIRUCHI SIVA: *

DR. V. SIVADASAN: *

Expunged as ordered by the Chair.

* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Will you listen to me? *...(Interruptions)...*Will you listen to me? Will you listen to me, please? Mr. Siva, please listen to me. *...(Interruptions)...* Please cool down. *...(Interruptions)...* Rule 258 is a general rule to raise a point of order. But, in relation to which rule you are objecting is to be mentioned which you have not done. That is why your point of order is not entertained. *...(Interruptions)...* Now, I am requesting the hon. Member to conclude his speech. *...(Interruptions)...*

SHRI AJAY PRATAP SINGH: Two minutes, Sir. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please. *...(Interruptions)...* Please cool down. *...(Interruptions)...* Please cool down. *...(Interruptions)...* A healthy discussion is going on health. *...(Interruptions)...* A healthy discussion is going on health. *...(Interruptions)...* It is a healthy discussion on health. *...(Interruptions)...* All of us are concerned. *...(Interruptions)...*

श्री अजय प्रताप सिंह: अब हरेक गांव के घर-घर में बिजली पहुंच गई। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Please continue. *...(Interruptions)...* Please continue. *...(Interruptions)...*

श्री अजय प्रताप सिंह : हर जगह बिजली पहुंचने का यह असर हुआ है कि उसके माध्यम से अब इलाज करना भी आसान हुआ है और लोगों की ज़िदंगी आसान हुई है। ज़िदंगी आसान हुई, तो बीमारियां भी कम पैदा हो रही हैं।...(**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA: *

DR. JOHN BRITTAS:

SHRI M. MOHAMED ABDULLA:

DR. V. SIVADASAN:

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please sit down. *...(Interruptions)...* Please sit down. *...(Interruptions)...* Other than what has been

* Not recorded.

spoken by Shri Ajay Pratap Singh, no other comments will go on record. ...*(Interruptions)*... अजय जी, आप बोलते रहिए।...(**व्यवधान**)...

श्री अजय प्रताप सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, बीमारियों का एक प्रमुख कारण यह था कि हमारी...(व्यवधान)...

SHRI TIRUCHI SIVA: *

DR. JOHN BRITTAS: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री अजय प्रताप सिंह : जीवन को आसान बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए मोदी सरकार ने आम आदमी के जीवन स्तर में जो परिवर्तन किया है, उसका असर भी उसके स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। अब बड़ी छोटी-सी बात है कि कोरोना महामारी आई। उस महामारी के समय पर चारों तरफ आपाधापी फैली।...(**समय की घंटी**)...

SHRI TIRUCHI SIVA: *

श्री अजय प्रताप सिंह : उस आपाधापी के समय पर ...(**व्यवधान**)... मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। लोगों को अच्छा भोजन, अच्छा जीवन स्तर, लोगों को अच्छी सुविधा देने के माध्यम से भी स्वास्थ्य का बहुत सारा अंतर आया है, इसलिए मैं यह समझता हूं...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : आप खत्म कीजिए।...(**व्यवधान**)...

SHRI TIRUCHI SIVA: *

श्री अजय प्रताप सिंह : मनोज झा जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, आज के समय में वह अप्रासंगिक है, अनावश्यक है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।...(**व्यवधान**)... सरकार इस विधेयक के बिना, इस अधिकार को प्रदान किए बिना भी बहुत अच्छा काम कर रही है।...(**व्यवधान**)... इन्हीं व्यवस्थाओं को और अच्छे तरीके से लागू करने में अगर हमारे विपक्षी साथी भी सहयोग करेंगे, तो हमारे यहां की स्वास्थ्य सेवाओं में भी निखार आएगा और आम आदमी की जो औसत आयु है, औसत ज़िदंगी है, वह और बेहतर होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)...

---

* Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Now, the hon. Minister to reply. ...*(Interruptions)*... Now the hon. Minister to reply. ...*(Interruptions)*... Please sit down. The hon. Minister to reply. ...*(Interruptions)*...

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (**डा. मनसुख मांडविया**) : उपसभाध्यक्ष महोदय, राइट टू हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट प्राइवेट मेम्बर्स बिल प्रो. मनोज कुमार झा जी लेकर आए हैं। कुल मिलाकर 15 से अधिक सम्माननीय सदस्यों ने इस पर अपनी बात रखी। मनोज झा जी बहुत विद्वान और सम्माननीय सदस्य हैं। जब वे अपनी बात को रख रहे थे, जिस परिप्रेक्ष्य में वे अपना विषय रख रहे थे, देश की वर्तमान स्थिति, हेल्थ के संदर्भ में...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : प्लीज़, शांत बैठिए। मंत्री जी अपना जवाब दे रहे हैं।

डा. मनसुख मांडविया : देश की परिस्थिति, दुनिया की हेल्थ के संदर्भ में भी सम्माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखीं। मैं स्वाभाविक तौर पर यह मानता हूं कि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिस पर मनोज झा जी और सभी सदस्यों की बात का एक सुर निकलता है कि लोगों को हेल्थकेयर अच्छी तरह से मिलना चाहिए, यानी कि हेल्थकेयर एक्सेसिबल और अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि लास्ट तबके के लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति न हो, जिसको ट्रीटमेंट की सुविधा न मिल पाए। एक बार मोदी जी ने अच्छी बात कही थी कि हमारी हेल्थ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी गरीब परिवार के सदस्यों को इलाज उपलब्ध न होने की दृष्टि से उसके यहां मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। उसको मेडिसिन सस्ती मिलनी चाहिए, उसको हेल्थकेयर, जहां वे रहते हैं, उसके नज़दीक मिलना चाहिए, उसको सेकेंडरी केयर और टर्शिएरी केयर भी अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। उसके लिए इतना ही सवाल है कि अर्पोच हॉलिस्टिक होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहूंगा और विस्तार से विषय भी बताऊंगा कि मोदी जी ने हमेशा किसी विषय को पृथक रूप में नहीं देखा है। वे हमेशा टोटल में सोचते हैं। सर्वग्राही दृष्टि से हेल्थ को हम कैसे एक्सेसिबल और अफोर्डेबल करें, उसके लिए मोदी जी द्वारा जो कार्ययोजना अमल में लाई गई है, वह कार्ययोजना, जो हमारे मनोज भाई ने कहा, वह उनकी और हमारे सदन के सम्माननीय सदस्यों की भावना है। यह भावना पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसीलिए हेल्थ को एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा गया है। इस देश में सालों तक हेल्थ को केवल ट्रीटमेंट के रूप में ही देखा गया है। हेल्थ को कभी डेवलपमेंट के साथ जोड़ा ही नहीं गया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मोदी जी ने हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ा है। देश के नागरिक स्वस्थ हैं, तो सोसाइटी स्वस्थ होगी। सोसाइटी, समाज स्वस्थ है, तो देश स्वस्थ होगा और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए समृद्ध राष्ट्र के लिए समाज स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और समाज को स्वस्थ रखने के लिए देश के नागरिक को हेल्थ सुविधा मिले, यह बहुत आवश्यक होता है। हॉलिस्टिक अप्रोच का नतीजा क्या निकला? माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, एक गरीब परिवार में जहां दिया नहीं जलता है, वहां दिया कैसे जले, एक

गरीब परिवार को घर कैसे मिले, उस घर में चूल्हा जलाने के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध हो, घर में बिजली हो, घर में हेल्थकेयर ऐक्सेस हो। मोदी जी ने कभी गरीबी उन्मूलन योजना को राजनीति से नहीं देखा, उसका कभी राजनीतिकरण नहीं किया। उन्होंने सैचुरेशन अप्रोच के साथ काम किया। मोदी जी ने कहा, 'देश के हर नागरिक', उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इस राज्य में बीजेपी की सरकार है, इस राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार है, इन लोगों ने हमें वोट दिया है, इन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है - ऐसा कभी मोदी जी ने नहीं कहा है। मोदी जी ने कहा है कि हर गरीब परिवार को अपना जीवन चलाने के लिए सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने इस सैचुरेशन के साथ काम करना शुरू किया। आज उसका नतीजा दिखने लगा है। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, तब देश का हेल्थ बजट 33 हज़ार करोड़ रुपये था। हमारी सरकार बनने के बाद, 2018-19 में यह बजट 58 परसेंट बढ़कर 52 हज़ार करोड़ रुपये का हो गया। हमने बजट को 58 परसेंट बढ़ाया। ...(**व्यवधान**)... उसके बाद बजट सतत बढ़ता गया और 2019-20 में वह 62 हज़ार करोड़ हुआ, 2021-22 में 71 हज़ार करोड़ हुआ और 2022-23 में 83 हज़ार करोड़ हुआ। हम धीरे-धीरे बजट बढ़ाते गए। 2017 में हमने हेल्थ पॉलिसी डिक्लेयर की। यहां एक सम्मानित सदस्य ने प्रश्न किया कि आपने जीडीपी के सापेक्ष में अपना बजट कितना बढ़ाया? माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सभी देशों का अपना-अपना मॉडल होता है। मैं मानता हूं कि दुनिया में जहां बेस्ट है, वहां से सीखना चाहिए। बेस्ट जिसका मॉडल है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके संबंध में मेरी कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है, लेकिन हर देश का अपना-अपना मॉडल होता है और मॉडल के तहत मुझे, ऐज़ ए मिनिस्टर कई लोग मिलने के लिए आते हैं और मुझे कहते हैं कि आपका हेल्थ का बजट, जैसा यहां की दुनिया का परिप्रेक्ष्य रखा गया, वैसे ही परिप्रेक्ष्य के साथ वे कहते हैं कि उसका 7 परसेंट है, उसका 8 परसेंट है, उसका 9 परसेंट है और हमारे देश का जीडीपी के सापेक्ष में 1.9 परसेंट बजट है, जो कि हमें बढ़ाना चाहिए। हमने तय किया है कि हम आने वाले दिनों में उसको 2.5 परसेंट तक ले जाएंगे और भविष्य में और भी आगे ले जाएंगे। ...(**व्यवधान**)... धीरे-धीरे हम देश में हेल्थ का बजट तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जब हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तब हमें अपने देश की स्ट्रेंथ और क्षमता को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस देश में हेल्थ कॉमर्स बाद में था, यहां हेल्थ को सेवा के रूप में देखा जाता है। हेल्थ हमारे लिए सेवा है। हेल्थ हमारे लिए सहयोग है, सपोर्ट है और यही परिप्रेक्ष्य है, जब दुनिया में कोविड क्राइसेस चल रहा था, फर्स्ट लॉकडाउन था, सेकंड लॉकडाउन था, फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन के दरमियान हम फॉर्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, दुनिया हमारे ऊपर अपेक्षा करके बैठी थी, दुनिया के पास मेडिसिन नहीं थी, दुनिया हर दिन इंडिया को कॉल करती थी, के प्रधान मंत्री जी को कॉल करते थे, हेल्थ मिनिस्टर को कॉल करते थे। मैं फार्मा देख रहा था। उस वक्त मोदी जी ने हमें निर्देश दिया था कि हमारे देश में मेडिसिन की किल्लत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना को मानने वाले लोग हैं, हम केवल लाभ की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम अपने घर के डोर पर लिखते हैं - शुभ लाभ। हम लाभ की भी बात करते हैं और शुभ की भी बात करते हैं। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा कल्याण हो - यह तो सभी लोग कहेंगे, प्राणी मात्र अपने लिए तो ऐसा सोचेगा, लेकिन यह हिंदुस्तान की परंपरा है, हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान की संस्कृति है कि हम अपना भी कल्याण चाहते हैं और दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए। महोदय, यह हमारी परंपरा रही है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बात को चरितार्थ

करने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि उस वक्त दुनिया भर से कॉल्स आती थीं, डेवलप्ड कंट्रीज के पास भी एज़िथ्रोमाइसिन नामक मेडिसिन नहीं थी। एक कंट्री में 15-15 दिनों तक एज़िथ्रोमाइसिन मेडिसिन नहीं थी, कॉल आता था कि एज़िथ्रोमाइसिन भेजिए। महोदय, मुझे एक कंट्री से कॉल आया, मैं उसका नाम यहाँ नहीं बोलूंगा कि हम आपको वेंटिलेटर देंगे, आप हमें मेडिसिन दो। तब मैंने कहा था कि आपके पास वेंटिलेटर है, तो अवश्य दीजिए, लेकिन मैं इस शर्त पर आपको नहीं दूंगा। अगर आप हमें वेंटिलेटर नहीं पहुंचाएंगे, तब भी हम आपको मेडिसिन उपलब्ध कराएंगे।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने उस वक्त 150 देशों को मेडिसिन उपलब्ध कराई थी। बात रही मॉडल की - जो मैं बता रहा था, जब मुझसे बाहर से आकर बात करते हैं कि यहाँ हेल्थ पर खर्च इतना है, यहाँ हेल्थ पर खर्च कितना है, वहाँ क्या मॉडल होगा आदि-आदि, तो मैं यही कहूंगा कि मुझे उसमें नहीं जाना है। तब मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था कि आप जिस कंट्री की बात कर रहे हैं, यदि वहाँ पर टीथ का इलाज कराना है, टीथ निकलवाना है, तो कितना खर्च होगा? उन्होंने मुझे बताया कि इस पर 200 से 500 डॉलर तक का खर्च लगेगा। मैंने कहा कि मेरे डॉक्टर्स और मेरे देश के अस्पताल 200 रुपये में इसका इलाज कर देंगे। हमें एक सापेक्ष में, परिप्रेक्ष्य में इंडिया के खर्च को मैप करना चाहिए। यह हमारी स्ट्रैंथ है, हम इस स्ट्रैंथ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं और इसीलिए हमारी हेल्थ एक्सेसिबल कैसे होगी, हमारी हेल्थकेयर कैसे अफोंडेबल होगा - इस पर आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने जो कार्ययोजना बनाई है, वह 4 पिलर की कार्ययोजना बनाई है। मनोज जी, आपको इस बात का सैटिस्फेक्शन होगा कि जिस तरह से काम करना शुरू हुआ है, वह बहुत अच्छा है। उसमें एक है - आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर. महोदय, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर क्या है? महोदय, देश में सभी प्राथमिक आरोग्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थकेयर सेंटर्स को हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स में कंवर्ट करने के लिए, 1 लाख 50 हज़ार हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कार्ययोजना बनाई गई है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर में क्या-क्या सुविधाएं होंगी - इसमें भारत सरकार राज्य सरकार के साथ सहयोग करेगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट बनाएंगे और 13 तरह की स्क्रीनिंग हो पाएगी। यदि वहाँ पर कोई मरीज इलाज के लिए आएगा, तो उसका इलाज भी हो जाएगा। वहाँ योग की क्लास भी चलेगी, वैलनेस के लिए सप्ताह में दो बार क्लास लगेगी, वहाँ पर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा, वहाँ सगर्भा महिला का ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उसकी हेल्थ की चिंता की जाएगी। वहाँ एनसीडी, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का परीक्षण किया जाएगा। यह हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर पर होगा। महोदय, 7-8 हज़ार की पॉप्युलेशन पर एक हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर होगा। यदि किसी महिला को ओरल कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर होगा, तो ऐसे तीन टाइप के कैंसर्स की स्क्रीनिंग भी हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर पर हो जाएगी।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने तय किया था कि 2017-18 में हम देश में 1 लाख, 50 हज़ार हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स बनाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम केवल बात नहीं करते हैं, हम उसे धरातल पर भी उतारते हैं। आज 1 लाख, 22 हज़ार हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स बन चुके हैं और दिसंबर तक ऐसे 1.5 लाख सेंटर्स देश की सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। यह कार्य योजना पूरे देश में चल रही है।

महोदय, इतना ही नहीं, एक होलिस्टिक अप्रोच के अनुसार कैसे काम होता है, मैं उस पर आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। महोदय, 'ई संजीवनी' प्लैटफॉर्म बनाया गया। इस 'ई संजीवनी' प्लैटफॉर्म से टेलीमेडिसिन, टेलीकंसल्टेशन कैसे किया जाएगा - मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि आज सभी हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स पर एक कम्प्यूटर दिया गया है, वहाँ पर लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको डेढ़ महीने पहले की बात बता रहा हूं। दिल्ली के नज़दीक हरियाणा में झज्जर नामक जगह पर एक कैंसर इंस्टिट्यूट बना हुआ है, एम्स का सब-सेंटर बना हुआ है। मैं वहां जा रहा था। रास्ते में मैंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का एक बोर्ड देखा, मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी अंदर ले ले। मैंने वहां जाना नहीं था, मेरा कोई कार्यक्रम नहीं था, कार्यक्रम का पार्ट नहीं था, मैं जा रहा था, पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देखा तो मैंने सोचा कि एज़ ए मिनिस्टर, हम सरकार में बैठकर जो सोच रहे हैं, सचमुच यहां उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, यहां कैसी सुविधा है, मैं देखना चाहता हूं।

जब मैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में गया, मुझे खुशी हुई, वहां एक डाक्टर साहब थे, उनको पता नहीं था कि मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं और आकर उसके बगल में बैठा हूं। उसके बगल में एक मरीज बैठा था, वह मरीज महिला थी, उसके साथ डाक्टर साहब बात कर रहे थे। बात करते-करते उनको ऐसा लगा कि मुझे और मार्गदर्शन की आवश्यकता है, मुझे और सुझाव की आवश्यकता है, उसके ज्ञान से उनको ऐसा लगा होगा कि मुझे एक्सपर्ट डॉक्टर की ओपिनियन की आवश्यकता है, वहां बैठे हुए डाक्टर एम.बी.बी.एस. डाक्टर थे, 'ई-संजीवनी' प्लेटफॉर्म के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट ने पी.जी.आई., चंडीगढ़ के साथ टाइ-अप किया है। पी.जी.आई. चंडीगढ़ के साथ तुरन्त ही वे 'ई-संजीवनी' प्लेटफॉर्म से जुड़ गये। स्पेशलिस्ट डाक्टर सामने बैठे थे, एक गाँव में गरीब मरीज डाक्टर साहब के बगल में बैठी थी। उन दोनों डॉक्टरों ने आपस में बातचीत की कि मरीज की यह-यह स्थिति है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ऐसा लगा कि मैं मरीज के साथ बातचीत करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा अपने कम्प्यूटर को मरीज के सामने मोड़िये, उन्होंने कम्प्यूटर को थोड़ा बायें करके मरीज के साथ स्पेशलिस्ट डाक्टर की बातचीत कराई और उसके आधार पर स्पेशलिस्ट डाक्टर साहब ने एम.बी.बी.एस. डॉक्टर साहब को कहा कि आप इस टाइप का प्रेस्क्रिप्शन लिख दो और कहो कि सात दिन के बाद फिर से आकर दिखा दे।

महोदय, तब सेटिस्फेक्शन होता है, जब एक गांव में रहने वाला गरीब मरीज एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आकर एक टर्शिएरी हॉस्पिटल के साथ जुड़कर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सलाह के आधार पर अपना ट्रीटमेंट करवाता है। उसका उद्देश्य है कि हम कैसे हेल्थ को एक्सेस कर रहे हैं। जब होलिस्टिक एप्रोच की बात होती है, तब हमें देश में डॉक्टर्स चाहिए, हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो बनाया, लेकिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए डॉक्टर्स चाहिए। अगर डॉक्टर्स चाहिए तो मेडिकल कॉलेज बढ़ाने चाहिए। जैसा यहां सम्मानित सदस्य बोल रहे थे, 622 से तकरीबन डबल मेडिकल कालेज हो गये, पहले हमारी सीट्स 51,000 थीं, आज केवल 7-8 साल में 1 लाख सीट्स हो गईं। 8 साल में 51 हजार से 1 लाख एम.बी.बी.एस. की सीट्स हमने उपलब्ध कराईं और तब जाकर हमें डाक्टर मिले। यही होलिस्टिक अप्रोच का मकसद होता है। इतना ही नहीं, हमें कम्पेरीज़न में डब्लू.एच.ओ. ने कहा है कि एक हज़ार की पॉप्यूलेशन पर एक

डाक्टर होना चाहिए। हमारे पास 13 लाख एम.बी.बी.एस. डॉक्टर्स हैं, 5.5 लाख आयुष डॉक्टर्स हैं। आज 800 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर्स इस देश के अंदर उपलब्ध है और वह देश की सेवा कर रहा है।

हमारे डाक्टरों की भी एक भावना है - जैसा मैंने कहा कि किस परिप्रेक्ष्य में हमारे लोग काम करते हैं - कोविड क्राइसिस में हमने यह भी देखा है। मेरी तो उस वक्त एक दिन में 10-10 मीटिंग्स दुनिया की कई कंट्रीज़ से होती थीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी मीटिंग्स हुआ करती थीं। डिप्टी चेयरमैन सर, कई जगह से ऐसा मैसेज आता था कि डॉक्टर साहब ड्यूटी पर नहीं आते थे, उनको मृत्यु का डर लगता था, लेकिन हिन्दुस्तान के डॉक्टरों ने ऐसा नहीं किया। हमारे मेडिकल स्टाफ ने, पैरा मेडिकल स्टाफ ने ऐसा नहीं किया, वे अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की सेवा में लगे रहे और देश को कोविड क्राइसिस से बचाया। यह होलिस्टिक एप्रोच का ही एक परिणाम है। एक पिलर के बारे में मैंने आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में बताया।

दूसरा पिलर मैंने बताया, 'आयुष्मान भारत' और 'जन आरोग्य योजना' आयुष्मान भारत के बारे में यहां सभी सदस्यों ने बोला भी है। 'आयुष्मान भारत योजना' का इम्प्लिमेंटेशन कैसे हो रहा है, दस करोड़ फैमिलीज़, यानी कि 50 करोड़ लोगों को एक परिवार में पांच लाख रुपये का हेल्थ एक्सेस देना - यह छोटी बात नहीं है। डा. राधा मोहन दास अग्रवाल जी जो बोल रहे थे, उसमें वे अपना विस्तृत विषय रख रहे थे। उसमें उन्होंने एक सूची बोली और मनोज जी को सामने देखकर कहा कि मनोज जी इतने-इतने कैटेगरी के लोगों को ऑलरेडी हेल्थ एक्सेस मिल चुका है, हैल्थ सिक्युरिटी मिल चुकी है, यानी कि जो आप चाहते हैं, यह कार्ययोजना ऑलरेडी आयुष्मान भारत योजना के मुताबिक उसका इम्प्लिमेंटेशन होना चालू हो गया है। जब यह बात आती है तो मैं बिहार का ही एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं, आज से एक-दो महीने पहले मेरा बिहार में प्रवास हुआ था, मैं रक्सोल गया था। मुझे रक्सौल में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करना था। उसके पहले जिसको सरकार की योजना, 'आयुष्मान भारत योजना' का लाभ मिला हो, ऐसी एक लाभार्थी महिला ने मंच पर आकर जिस भाषा में अपनी बात बताई, मैं उसकी ही भाषा में बोलना चाहता हूँ। उसने कहा कि 6-7 महीने पहले मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मैं ससुराल गई। एक दिन मेरी साँस फूलने लगी, मुझे अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको हार्ट की बीमारी है। हमने हार्ट की बीमारी का इलाज कराने के लिए पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसमें डेढ़ लाख के नजदीक खर्च आएगा। उसके पास यह सुविधा नहीं थी। उसके ससुराल पक्ष के लोग उसका ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए, तो ससुराल पक्ष ने उसको छोड़ दिया। वह मायके गई। पिताजी भी गरीब परिवार से थे। किसी ने उसको बताया कि आप 'आयुष्मान भारत योजना' का कार्ड बनवाओ। वह महिला अपनी बात बोल रही थी कि मैंने 'आयुष्मान भारत कार्ड' बनवाया। मैं एक प्राइवेट अस्पताल में गई, जो 'आयुष्मान भारत योजना' में रजिस्टर हुआ था। मैं वहाँ कार्ड लेकर गई, मैंने कार्ड दिखाया, मुझे एडमिट कर दिया गया, मेरा सारा इलाज हो गया और मुझे घर पहुँचने तक एक रुपए का भी खर्च नहीं हुआ, मैं बच गई। बाद में उसने कहा कि मैं स्वस्थ होकर आपके सामने खड़ी हूँ और मेरे ससुराल पक्ष ने भी मुझे स्वीकार कर लिया। यह 'आयुष्मान भारत योजना' की सक्सेस स्टोरी है। इस योजना के माध्यम से एक टाइप की यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिल रही है। कई राज्यों ने उससे भी आगे जाकर अपनी ओर से और भी योजनाएँ लागू की हैं। मैं उसकी भी सराहना करता हूँ।

फूड सिक्योरिटी के डेटा के आधार पर आपने यहाँ हेल्थ सिक्योरिटी देने की बात की है, यह भी सराहनीय है। 2 हजार साल तक कभी हम परतंत्र रहे, कभी हूणों ने शासन किया, कभी शकों ने शासन किया, मुगल वंश, खिलजी वंश से लेकर तुगलक वंश, सब लोगों ने शासन किया, 240 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, हमें इस मानसिकता से बाहर आना है। हमें अपनी शक्ति को समझना है। देश में ब्रेन पॉवर और मैनपॉवर की कभी कमी नहीं थी और न ही है। यह उसकी ही सक्सेस स्टोरी है। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, हमारे देश में अपार क्षमता की संभावनाएँ हैं। इस देश में बेस्ट डॉक्टर्स भी हैं, इस देश में बेस्ट साइंटिस्ट्स भी हैं, लेकिन आजादी के बाद भी जब दुनिया में किसी वैक्सीन के ऊपर रिसर्च होता था, तो रिसर्च होने के बाद 10-15 साल के बाद ही वह वैक्सीन हिन्दुस्तान में आती थी। हमारे साइंटिस्ट्स में कमी थी, ऐसा नहीं था। हमें उनके ऊपर कॉन्फ़िडेंस नहीं था कि हम उनके ऊपर भरोसा करें। यही सक्सेस स्टोरी है। जब कोविड क्राइसिस शुरू हुआ, उस समय जब साइंटिस्ट्स लोगों ने मोदी जी को बताया कि इसके लिए तो वैक्सीन चाहिए, तब मोदी जी ने भारत के नामांकित साइंटिस्ट्स को बुलाया, वैज्ञानिकों को बुलाया और कहा कि क्या हम वैक्सीन बना सकते हैं, क्या हम इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, तब हमारे साइंटिस्ट्स ने कहा कि हम इसे करके देंगे। हमने अपने साइंटिस्ट्स पर भरोसा किया। हमारे ये ही साइंटिस्ट्स कोरोना की वैक्सीन के रिसर्च पर लग गए। दुनिया ने रिसर्च की, हमारे साइंटिस्ट्स ने भी रिसर्च की। दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। जब दुनिया ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया, तो 16 जनवरी, 2021 को भारत ने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू किया। इतना ही नहीं, 9 महीने में 100 करोड़ डोज़ और 18 महीने में 200 करोड़ डोज़ लगाने के साथ ही हमने इसका विश्व वितरण किया, यह तो एक बात है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह शक्ति 'देश की शक्ति' है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यह शक्ति 'देश की शक्ति' है। यह छोटी बात नहीं है। 'देश की शक्ति' शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप मैनेजमेंट करते हैं, तो मैनेजमेंट के कई पाट्र्स होते हैं। केवल वैक्सीन का रिसर्च हो गया, वैक्सीन एडमिनिस्टर हो गयी, इतना पता है, लेकिन एक दिन में डेढ़ लाख वैक्सीनेशन सेंटर्स का चलना, जब वैक्सीनेशन सेंटर्स चलते हैं, तो टाइम पर उनको वैक्सीन पहुँचाना, वैक्सीन पहुँच गयी, तो वैक्सीनेशन के लिए हमारे वैक्सीनेशन स्टाफ का उपस्थित होना, यह सब जरूरी है। अगर वैक्सीनेशन स्टाफ उपस्थित हो गया, वैक्सीन पहुंच गई, तो वैक्सीन लगाने के लिए सीरिंज भी चाहिए, नीडल भी चाहिए। वाइस चेयरमैन सर, 18 महीने में 200 करोड़ डोज़ेज़ एडमिनिस्टर करने की जर्नी के दरमियान कभी भी ...(**व्यवधान**)...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Sir, ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No. ...*(Interruptions)*... Please continue. ...*(Interruptions)*...

डा. मनसुख मांडविया : डा. साहिबा, आप पहले मुझे बोल लेने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please do not disturb. *...(Interruptions)...*

डा. मनसुख मांडविया : इसका फायदा यह होगा ...(**व्यवधान**)... I will listen to you. *...(Interruptions)...* You can speak after my reply. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No. *...(Interruptions)...* Allow the Minister to complete. *...(Interruptions)...*

डा. मनसुख मांडविया : सर, मेरे पास ऐसी-ऐसी इन्फॉर्मेशंस है, जिससे सदन को भी वह समझने में आसानी होगी, जो कोविड क्राइसिज़ के दौरान हुआ। कृपया पहले मुझे सुन लें, बाद में आपकी कोई क्वेरीज़ होंगी, तो मैं रिप्लाई भी करूंगा।

महोदय, कोविड काल के दरमियान कहीं भी सीरिंज की कमी नहीं हुई, कहीं भी नीडल की कमी नहीं हुई। किसी को किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा कि वे वैक्सीनेशन सेंटर पर गए और वहां सीरिंज नहीं थी, नीडल नहीं थी, जिसके कारण उसका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। भारत का कोविड मैनेजमेंट बेस्ट था और इसकी सराहना सारी दुनिया में हुई। ...(**व्यवधान**)... कुछ समय पहले मैं ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No. *...(Interruptions)...* Please do not disturb. *...(Interruptions)...*

डा. मनसुख मांडविया : कुछ समय पहले मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गया था, जहां मुझे बिल गेट्स और अन्य कई लोग मिले। जब उनके साथ वन-टू-वन मीटिंग होती थी, तो मुझे गौरव होता था, क्योंकि पहले वे इंडिया के लिए अभिनन्दन कहते थे और कहते थे कि आपने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया है, बेस्ट वैक्सीनेशन मैनेजमेंट किया।

सर, एक समय था, जब कोविड की शुरुआत के दिनों में डब्ल्यूएचओ या इंटरनेशनल प्लैटफॉर्म्स पर मीटिंग होती थी, तो उनको यह चिंता रहती थी कि इंडिया जैसे बड़े देश में, जहां 130 करोड़ की जनसंख्या है, ह्यूज डायवर्सिटी है, इतने बड़े देश में ये लोग कोविड मैनेजमेंट कैसे करेंगे? इंडिया में कितनी ज्यादा डेथ्स होंगी, इस आकलन के आधार पर ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर अंदाज़ा लगाते थे कि वैश्विक परिस्थिति क्या होगी। लेकिन नतीजा यह निकला कि इंडिया ने बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव और बेस्ट कोविड मैनेजमेंट करके देश को कोरोना की थर्ड सर्ज से भी बचा लिया। जब ओमिक्रॉन आया, उस समय भी दुनिया भर में बहुत अधिक लोग मरे। दुनिया में ओमिक्रॉन की सेकंड वेव में जितना इफेक्ट पड़ा था, उतना ही इफेक्ट थर्ड वेव में भी पड़ा। लेकिन उस वक्त भारत में 85 प्रतिशत लोग वैक्सीनेटेड थे, इसलिए जब यहां ओमिक्रॉन की थर्ड सर्ज आई, तो उस थर्ड सर्ज में भी यहां बहुत कम लोगों की मृत्यु हुई। इस तरह हम कोविड क्राइसेज़ से बहुत सफलता से लड़ाई जीत पाए। यह हमारे देश की होलिस्टिक हेल्थकेयर के लिए किए गए प्रयास का परिणाम है, लेकिन मेरा मानना है कि हर स्थिति से हमें सीखना चाहिए।

महोदय, कोविड क्राइसेज़ ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट कर लिया तो हम सैटिस्फाइड हो गए, संतुष्ट हो गए और आगे कुछ नहीं करना है। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि हमें आगे बहुत कुछ करना है। आज हमारे देश में हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ करने की संभावना है और हमें बहुत कुछ करना है। हमने देखा कि कोविड क्राइसेज़ के दरमियान हमारे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर में क्या-क्या कमियां पाई गईं, उनका हमने डिटेल्ड अध्ययन किया। डिटेल्ड अध्ययन के आधार पर आयुष्मान भारत के थर्ड पिलर, आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन पर पांच साल में 64 हजार करोड़ रुपये खर्च करना तय किया गया, यानी एक डिस्ट्रिक्ट पर ऑन एन एवरेज 100 करोड़ रुपये। मेरा आप सभी से आग्रह है और विनती भी है कि आप सब लोग अपनी-अपनी कॉंस्टिट्युएंसीज़ में, अपने क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से, स्टेट हेल्थ ऑफिसर से यह पूछिए कि इन 100 करोड़ रुपयों का आपके डिस्ट्रिक्ट में कहां पर यूज़ होना है। आप उनसे पूछिए कि हमने यहां के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर 100 करोड़ रुपये खर्च करने की प्लानिंग की है, तो उसका उपयोग कैसे होना है? इसके लिए आप देखिए कि ब्लॉक लेवल पर, सरकारी स्तर पर लैबोरेटरीज़ स्थापित की जाएं। आप देखिए कि अगर आपके यहां कोई पेंडेमिक या कोई डिज़ीज़ चल रहा है, तो उसका कंटीन्युअस सर्विलेंस होता रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में 100 बेड्स की एक क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जाए। अगर भविष्य में कभी पेंडेमिक जैसी स्थिति पैदा हो जाए, तो वैसी स्थिति का सामना करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए,जिसके लिए क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेकेंडरी लेवल की एक लैबोरेटरी बनाई जाएगी, जिस लेबोरेटरी में 130 से अधिक टैस्टिंग्ज़ हो पाएंगी। इसके साथ एक टाइप का सर्विलेंस भी वहां से हो जाए कि यहां जो कुल मरीज आते हैं, वे किस टाइप की डिजीज़ के आते हैं और उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग की वहां व्यवस्था हो, ताकि यह पता चल जाए कि कोई नई बीमारी तो नहीं फैल रही है, यदि कोई बीमारी फैल रही है, तो कैसी स्थिति में फैल रही है, उसका आकलन करके उसके ऊपर विस्तृत स्टडी की जाए। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिटिकल केयर यूनिट भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छी लेबोरेटरी हो। इसके अलावा स्टेट लेवल पर और रीजनल लेवल पर एक स्ट्रांग सर्विलेंस सिस्टम यूनिट बनाया जाए। ऐसा करके आगामी पांच साल में 64 हजार करोड़ रुपये खर्च करके, जो हमारा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसको एक नई हाइट देने के लिए हमने एक कार्य योजना बनाई है।

महोदय, पहले कोविड-19 में 15 हजार करोड़ रुपये... चूंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है, यहां यह बात भी आई थी कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कहकर हमें छूट नहीं जाना चाहिए। यह देश का सब्जेक्ट है, कोई स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, हम सबका सब्जेक्ट है। हेल्थ देश के हर नागरिक के साथ जुड़ी हुई है और अल्टिमेटली सेन्टर काम करता है, तो स्टेट्स के साथ ही काम करता है, स्टेट भी सेन्टर का ही एक पार्ट है और इसलिए स्टेट और सेन्टर कभी अलग नहीं हो सकते, कोई भी कार्य-योजना बनती है, तो स्टेट्स के द्वारा ही इम्प्लिमेंट होनी है, भारत सरकार पैसा दे या राज्य सरकार पैसा दे, पैसा भले ही किसी का खर्च हो, लेकिन हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्राँग होना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कार्य योजना चल रही है और उसका इम्प्लिमेंटेशन हमने करना चालू कर दिया है।

फोर्थ पिलर 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन', यह एक एडवांस सोच है। इस सेक्टर में हम दुनिया से आगे की सोच लेकर चल रहे हैं। 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' एक ऐसी फेसिलिटी है, जिसमें आप और मैं सभी लोग अपना आयुष्मान भारत डिजिटल अकाउंट ओपन करायें। एक बार हमने डिजिटल अकाउंट ओपन कर लिया। जैसे आज आप फाइल लेकर घूमते हैं, आप एनेक्सी के सीजीएचएस में अपने हेल्थ चैक अप के लिए जाएंगे, तो वहां तुरंत आपकी फाइल मंगायेंगे और फाइल लेकर वे आगे-पीछे की हिस्ट्री देखेंगे, उसमें आपकी हिस्ट्री होती है, लेकिन डिजिटल मिशन में सारे देश का हेल्थ डेटा रखने की बात है। आज बीस करोड़ से अधिक लोगों ने हेल्थ अकाउंट ओपन करा लिया है। आपका हैल्थ एकाउंट ओपन हो गया, तो डिजिटल मिशन के साथ लैबोरेटरी भी जुड़ी हुई हैं, अस्पताल भी जुड़े हैं, डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं और यदि एक नागरिक के रूप में आप भी उसके साथ जुड़ जाएं और जुड़कर देखें कि उसका उपयोग कैसे करना है। आपका डिजिटल हेल्थ अकाउंट है, आप डॉक्टर साहब के पास गये, आप डॉक्टर को कहेंगे कि मेरा डिजिटल हेल्थ अकाउंट नम्बर सो एंड सो है। आपने वह नम्बर दे दिया, तुरंत वे लॉग इन करेंगे, तो तुरंत ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। आप उनको ओटीपी देंगे ...(**व्यवधान**)... आप मेरी बात सुनिये, यह उपयोगी बात है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI BIKAS RANJAN BHATTACHARYYA (West Bengal): Please speak on the subject. ...*(Interruptions)*...

डा. मनसुख मांडविया : यह आपके लिए उपयोगी होगा ...(**व्यवधान**)... डिजिटल मिशन का इम्प्लिमेंटेशन कैसे होता है, यह बात आपके लिए उपयोगी होगी, अगर इसे समझो तो अच्छा है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): He is speaking about Ayushman Bharat. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please. ...*(Interruptions)*... Don't disturb.

डा. मनसुख मांडविया : महोदय, यह विषय अच्छा है, इसलिए...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please don't get into any controversy. ...*(Interruptions)*... Please.

डा. मनसुख मांडविया : डिजिटल मिशन में आपने डॉक्टर साहब को अपना नम्बर दिया, डॉक्टर साहब ने लॉग इन किया, लॉग इन करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया, आप जब ओटीपी एंटर करेंगे, तो तुरंत ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपका अकाउंट ओपन होते ही आपकी पूरी फाइल खुल जाएगी, आपने किस लैबोरेटरी में टैस्ट्स कराये हैं, आपने भूतकाल में

क्या-क्या ट्रीटमेंट लिया है, आपकी लैब रिपोर्ट्स क्या हैं, यह सारा डॉक्टर साहब देख पायेंगे और डॉक्टर साहब के देखने के बाद ...(**व्यवधान**)... मैं यहाँ भी देख रहा था।...(**व्यवधान**)...

SHRI BIKASH RANJAN BHATTACHARYYA: Sir, even school children know this. ...*(Interruptions)*... You don't have to waste time speaking these things. ...*(Interruptions)*...

DR. MANSUKH MANDAVIYA: One minute. ...*(Interruptions)*... I am not wasting time. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): The Minister is not yielding. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Sorry; it is not wasting time. I am giving important information. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Yes. ...*(Interruptions)*... Please listen. ...*(Interruptions)*...

डा. मनसुख मांडविया : जब आपका अकाउंट ओपन होगा, तो डॉक्टर साहब आपकी रिपोर्ट देखेंगे, आपका इलाज करेंगे, उसके बाद आपके अकाउंट को लॉगआउट कर देंगे। जब एक आर आपका अकाउंट लॉगआउट कर दिया गया, तो उसको कोई दोबारा ओपन नहीं कर पाएगा। जब ओपन करना होगा, तो आपके पास ओटीपी आएगा और अगर आप वह ओटीपी देंगे, तभी डॉक्टर साहब आपका अकाउंट ओपन कर पाएँगे यानी आपकी हेल्थ की प्राइवेसी भी रहेगी। हमने ऐसा करके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्य योजना चलाई है। सभी सम्माननीय सदस्यों से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें ताकि भविष्य में आपको फाइल लेकर घूमना न पड़े। आपकी फाइल डिजिटल मिशन के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर में रहेगी और सारे डेटा की भी प्राइवेसी रहेगी। इस दृष्टि से हमने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्य योजना बनाई है, जिसका लाभ सबको मिलेगा।

महोदय, हमने आयुष्मान भारत के चार पिलर्स के माध्यम से देश के नागरिक की हेल्थ सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की, उसका एक रोडमैप बताया। उसके आगे जाकर कई सदस्यों ने बहुत अच्छी बात कही। जब हमें हॉलिस्टिक अप्रोच से काम करना है, तो उसके साथ हमारा स्वच्छ भारत अभियान भी जुड़ा हुआ है। महात्मा गाँधी जी ने कहा था, जहाँ स्वच्छता, वहाँ प्रभुता। महात्मा गाँधी जी ने स्वच्छता की बात इसलिए की थी,...(**व्यवधान**).. वह हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ विषय है। हेल्थ की सुरक्षा के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत सारे देश में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। हर घर में शौचालय हो, टॉयलेट हो और किसी फैमिली के किसी सदस्य को टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जाना पड़े - हमने यह सुनिश्चित किया है। अभी चल रहा है - हर

घर जल योजना - यह कोई छोटी बात नहीं है। शुद्ध पेयजल हर घर में उपलब्ध हो जाने से भी हमारी हेल्थ को सुरक्षा मिलेगी।

सर, अभी तो बहुत कुछ कहने जैसा है। देश में सस्ती दवा मिले, उसके लिए फार्मा मिनिस्ट्री के द्वारा हमने प्रयास किया। Myself is Pharma Minister also. मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ सब लोगों ने अपने भाषण में कहा कि देश में जेनेरिक मेडिसिन के स्टोर से फायदा हुआ है। मार्केट में कैंसर की मेडिसिन लेने जाएँ, तो वह पाँच सौ रुपए की मिलती है, लेकिन वही मेडिसिन जन औषधि केन्द्र में 60-70 रुपए में मिल जाएगी, एकदम सस्ती, लेकिन क्वालिटी की। आज देश में जन औषधि केन्द्र के द्वारा मेडिसिन उपलब्ध हो रही है। हमारे देश में क्या होता था? अमेरिका चार टैब्लेट्स खाता था, तो उनमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक टैब्लेट खाता था। दुनिया 6 टैब्लेट्स खाती थी, तो उनमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक टैब्लेट खाती थी और हम ब्रांडेड खाते थे और उसका प्राइस बहुत अधिक होता था। जब जन औषधि केन्द्र का अभियान चला, उसके पहले देश में जेनेरिक मेडिसिन का शेयर केवल 2 से 3 परसेंट था और आज वह बढ़ कर 20 परसेंट से ज्यादा हो गया है। इसके कारण हेल्थ अफोर्डेबल हो रहा है। आज 20 लाख लोग प्रतिदिन जन औषधि केन्द्र में जाते हैं। वहाँ उनको सस्ती दवाई मिलती है। रोज कमा कर रोज खर्च करने वाले परिवार में जब कोई बीमारी आती है, तो उसको सस्ती दवा मिले - यह भी बहुत आवश्यक होता है, इसलिए सम्माननीय सदस्य मनोज झा जी ने जो भाव व्यक्त किया है, मैं उनके भाव से सहमत हूँ। सभी को हेल्थ केयर मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर का एक्सेस होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है और इस पर पाँच घंटे तक बहस चली, ढाई घंटे last to last week ago और ढाई घंटे आज चली। इस विषय पर बहुत महत्वपूर्ण बहस हुई है। हम आपके भाव से सहमत हैं। आपने जो भावना व्यक्त की है कि हेल्थ एक्सेसेबल हो और उसके लिए हमने जो प्रयास किया है, आज हमने उसे भी व्यक्त किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें आने वाले दिनों में आपका और सभी सम्माननीय सदस्यों का सुझाव मिलता रहना चाहिए, ताकि हम और जोश से हेल्थ को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना सकें और हमारे मनोज भाई की जो भावना है, उस भावना को अच्छी तरह से चरितार्थ कर सकें। जिस दिशा में मनोज भाई सोचते हैं, हम भी उसी दिशा में सोचते हैं, इसलिए मनोज भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपकी भावना है, हम उस भावना के मुताबिक काम कर रहे हैं, इसलिए आप अपना बिल वापस ले लीजिए। आपकी भावना को पूरा करने के लिए हम हमेशा सतर्क रहेंगे और कोशिश भी करते रहेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Thank you. Now, Prof. Manoj Kumar Jha. ...*(Interruptions)*...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please. ...*(Interruptions)*...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Sir, he has agreed to answer.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please. ...*(Interruptions)*... Now, Prof. Manoj Kumar Jha. ...*(Interruptions)*... I have called... ...*(Interruptions)*...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Sir, on the Bill, he said that he will answer.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): It is because time is not there. That is the problem. ...*(Interruptions)*...

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: Sir, you allowed that for two hours and now, this....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): I am not seeking advice from him. ...*(Interruptions)*...

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Bill will be carried on for the next Session. He will have more time. In the next Session, you can speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Is the Minister ready to clarify any point? ...*(Interruptions)*...

DR. MANSUKH MANDAVIYA: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Okay, please.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: In the Minister's speech, he has mentioned the vaccine centers, India was ready to do it. Our Prime Minister was asking from all the scientists that whether we could do the vaccine manufacturing in India. When the Government of Tamil Nadu, under the leadership of Shri M.K. Stalin has asked for vaccine to be produced in Tamil Nadu in Chengalpet where the vaccine centre was very much there with all the infrastructure and everything, it was not awarded by our Prime Minister. It was not even considered by the Union Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): What clarification do you want to ask?

DR. KANIMOZHI NVN SOMU: One more thing, on digitalization, our hon. Minister was talking about digitalization of the health records of all the people all over the

country. It is a welcome step. But, how is it going to happen in the remote areas where only *Anganwadi* workers go and reach the patients, in the villages and tribal areas who don't know how to use even a mobile phone? So, I want the hon. Minister to respond, Sir, through you, on these two things.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Are you going to respond? ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, please listen to me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No; please sit down.

DR. JOHN BRITTAS: Sir, one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No, no. ...*(Interruptions)*... No further. ...*(Interruptions)*... No further. ...*(Interruptions)*... No, please sit down. ...*(Interruptions)*... No further. ...*(Interruptions)*... No further. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, one minute, he is yielding.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No, we don't have time. ...*(Interruptions)*... We don't have time. ...*(Interruptions)*... Sorry. ...*(Interruptions)*...No, sorry. ...*(Interruptions)*... Sorry. ...*(Interruptions)*...Sorry. ...*(Interruptions)*... No. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: Sir, one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please.

डा. मनसुख मांडविया : सर, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को करनी है, इसके लिए हमने कभी किसी को मना नहीं किया है। ...(**व्यवधान**)... हमने तो इसे प्रोत्साहित भी किया है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपने पीएसयू के साथ आ सकती है। हमारे पास महाराष्ट्र से 'हैफकीन' आई थी और हमने उसे आर्थिक सहयोग दिया था, not only for Government, बल्कि जब प्राइवेट इंस्टिट्यूट्स ने भी वैक्सीन रिसर्च के लिए सपोर्ट माँगा था, तब हमने उन्हें भी सपोर्ट किया था। अभी भी मंकीपॉक्स वैक्सीन की रिसर्च के लिए एक ईओआई निकाला गया है। जो स्टेट गवर्नमेंट मंकीपॉक्स वैक्सीन की रिसर्च में हिस्सेदारी लेना चाहती है, तो वह अवश्य हिस्सा ले सकती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Okay, that is all. ...*(Interruptions)*... Now, Prof. Manoj Kumar Jha. ...*(Interruptions)*... You have only two minutes to speak. ...*(Interruptions)*...

PROF. MANOJ KUMAR JHA: Sir, I agree. ...*(Interruptions)*... उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मुझसे आग्रह किया, उन्होंने समग्रतम बात रखी कि मैं बिल वापस ले लूँ। सर, दिल तो नहीं कह रहा है कि बिल वापस ले लूँ, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा है, तो यह दिल और दिमाग का पुराना झगड़ा है। बहरहाल, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आंकड़े बड़े मिसलीडिंग होते हैं। ग्रेजुएशन में समझा था कि आप कहिए कि इस बार 48 परसेंट था, अगली बार 58 किया। टोटल बजटरी आउटले का क्या प्रपोर्शन है, यह महत्वपूर्ण है और अगर आप इसे देखते हैं, तो चिंताजनक तस्वीरें हैं।

सर, केरल की बहुत चर्चा हुई। वहाँ पर बहुत इफेक्टिव सिस्टम है, लेकिन जब हम राइट टू हेल्थ की बात कर रहे हैं, जब राइट टू एजुकेशन की बात हुई थी, तब हाउस में इसी तरह की चर्चा हुई थी कि क्या जरूरत है। यह बिल्डिंग बना देना, कैम्पेन चला देना - 'चलो सब स्कूल की ओर', लेकिन राइट टू एजुकेशन को एक लेजिस्लेटिव फ्रेम देना, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

सर, हमारे माननीय सदस्य अजय जी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी के विषय में बोल रहे थे। सचमुच, they are the carriers of health system.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Time is over. Sorry; time is over. ...*(Interruptions)*...

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, फिर इसे कन्टीन्यू करा दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): This will be continued. No problem.

प्रो. मनोज कुमार झा : शुक्रिया, सर।

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Now, the Bhagat Singh National Urban Employment Guarantee Bill, 2022. Shri Binoy Viswam to move for leave to introduce the Bill.

The Bhagat Singh National Urban Employment Guarantee Bill, 2022

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I move for leave to introduce a Bill to provide for the enhancement of livelihood security of the households in urban areas of the country by formulation of the Bhagat Singh National Urban Employment Guarantee Scheme